सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 268, नई दिल्ली । शनिवार, 07 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया

06 समान शिक्षा समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

08 ओडिशा की महिलाओं ने रचा नया ट्रेंड : : सुभद्रा योजोना से रुपये लेने की इंकार किया

15 दिसंबर 2024 से यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करने के लिए लागू हो रही हैं नई लागू स्पीड लिमिट। जाने नई स्पीड के बारे में, नहीं तो हो जाएगा नुकसान

यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से लागू होगी नई स्पीड लिमिट

संजय बाटला

भारत देश में सड़क के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग एक्सप्रेसवे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई एक्सप्रेसवे हैं। जिनमें ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाने के लिए बना यमुना एक्सप्रेसवे प्रमुख एक्सप्रेस में है और रोजाना 35 लाख से भी ज्यादा वाहन यमुना एक्सप्रेसवे से होकर गुजरते हैं। जिन लोगों को दिल्ली, नोएडा से आगरा जाना होता है वह इस एक्सप्रेस वे का प्रयोग करते है। लेकिन अगर आप दिसंबर के महीने में यमुना एक्सप्रेस वे से ट्रैवल करने वाले हैं तो हो जाए सावधान क्योंकि प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाने के लिए रफ्तार के नियमों में बदलाव कर दिया है जो 15 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। आगे से यमुना एक्सप्रेसवे के सफर पर निकले तो स्पीड लिमिट पता करके ही निकले।

15 दिसंबर से नई स्पीड लिमिट यमुना एक्सप्रेस वे पर रोजाना 35 लाख से भी ज्यादा वाहन दौड़ते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में इनकी संख्या कम हो जाती है क्योंकि सर्दियों में इसपर खूब कोहरा होता है। ऐसे में गाड़ी चला कर ले जाना एक मुश्किल काम हो जाता है। विजिबिलिटी का भी काफी इशू रहता है जिस कारण दुर्घटना होने की संख्या भी काफी बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए यमुना विकास प्राधिकरण की ओर से यमुना एक्सप्रेसवे से होकर जाने वाले वाहनों के लिए नई स्पीड तय कर दी गई है। अब हल्के वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तय की गई है और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तय की गई है।

नए स्पीड लिमिट नियमों का पालन नहीं किया तो लगेगा भारी जुर्माना बता दें अगर कोई भी वाहन एक्सप्रेसवे पर तय की गई स्पीड लिमिट से ज्यादा की स्पीड पर गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो वाहन चालक पर जुर्माना लगाया जाता है। भारी वाहन चालक स्पीड लिमिट को तोड़ता है तो उस पर 4000 रुपये और हल्के वाहनों पर नियम तोड़ने के एवज में 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले 11 वाहन पेट्रोलिंग के लिए थे जो अब बढ़ाकर 15 कर दिए गए है, साथ ही 6 एंबुलेंस, 6 क्रेन और 6 दमकल गाड़ियां भी एक्सप्रेसवे पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति पर तुरंत सहायता मुहैया करवाई जा सके

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

अब सीएम आवास से किंग्सवे कैंप तक का सफर आसान, इन इलाकों को जाम मुक्त कराने की तैयारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से मॉल रोड होते हुए किंग्सवे कैंप तक का सफर अब जाम मुक्त होने जा रहा है। इस 4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 11 ट्रैफिक सिग्नल हैं जिससे अक्सर जाम लगता है। अब इस मार्ग को सिग्नल मुक्त करने और यू-टर्न व्यवस्था बनाने की योजना है। इससे न केवल यातायात सुचारू होगा बल्कि ईंधन की बचत प्रदूषण में कमी और अपराध में भी कमी आएगी।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री आवास से माल रोड़ होते हुए किंग्सवे कैंप के बीच सड़क मार्ग सिग्नल मुक्त करने की तैयारी है। इस मार्ग को जाम मुक्त करने के साथ यहां यू-टर्न व्यवस्था के लिए योजना बनाई गई है। महज चार किमी लंबे इस मार्ग पर छोटे बड़े 11 ट्रैफिक सिग्नल हैं। इसके लिए उत्तरी रेंज के डीसीपी ट्रैफिक ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) को संयुक्त निरीक्षण करने के लिए पत्र लिखा है। इससे यातायात जाम में राहत मिल सकती है।

राजधानी पाश इलाके से दिल्ली विश्वविद्यालय होते हुए किंग्सवे कैंप जाने वाले इस मार्ग पर हमेशा यातायात रहता है। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाल बत्ती होने से जाम लंबी लंबी कतारें लगती रहती है। इसे सुचारू बनाने के लिए योजना तैयार की गई है। उत्तरी रेंज के यातायात पुलिस उपायुक्त ने सीआरआरआई को भेजा है।

चार किमी लंबे मार्ग पर 11 ट्रैफिक सिगन्न

सुगम व सुरक्षित यातायात के लिए काम करने वाले एनजीओ गुरु हनुमान सोसायटी आफ भारत के राष्ट्रीय महासचिव डा अतुल रंजीत कुमार ने बताया कि इस चार किमी लंबे मार्ग पर 11 ट्रैफिक सिगन्न हैं, जिसमें सीएम आवास, विधानसभा, सिविल लाइंस थाना, खैबर पास, मॉल रोड, डीएमआरसी ऑफिस, डीयू कैंपस मोड़, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन।

प्रबिना पी, डीसीपी
यहां पर हैं ट्रैफिक सिग्नल
सीएम आवास
विधानसभा
सिविल लाइंस थाना
खैबर पास
मॉल रोड
डीएमआरसी ऑफिस
डीयू कैंपस मोड़
जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन।

खालसा कॉलेज, हकीकत नगर, किंग्सवे कैंप में यातायात को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल हैं। इन सभी सिग्नल को खत्म कर 14 से 15 छोटे-बड़े यूटर्न बनाने की योजना है।

दिल्ली में व्यवसायिक श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण जल्द ही करने लगेगे वाहन डीलर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो दिल्ली परिवहन विभाग की संचालन शाखा लगभग निजी वाहनों की तर्ज पर व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण को भी वाहन निर्माता/ वाहन डीलर्स को देने की अपनी प्रक्रिया पूरी कर चुका है, ओर जल्द ही दिल्ली में पंजीकृत वाहन डीलर व्यवसायिक वाहन खरीदने वालो को वाहन पंजीकृत करके पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने लगेगे।

सुनने और देखने में यह खबर जनहित में प्रतीत होती है पर व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण की बात समझे तो यह जनता की सुरक्षा से संबंधित है।

मोटर वाहन नियम के अनुसार अर्ध-न्यायिक शक्ति (Quasi judicial Power) प्राप्त अधिकारी ही वाहन पंजीकरण, वाहन के चलने के आवश्यक दस्तावेज परमिट, वाहन जांच प्रमाण पत्र और वाहन चलाने के लिए अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकता है क्योंकि यह जनता की सुरक्षा से जुड़ा सीधा मुद्दा है। इसके अलावा दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि में प्रयोग होने वाले वाहनों खास तौर से व्यवसायिक गतिविधि में शामिल सवारी वाहनों के प्रति सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया, उच्च न्यायालय दिल्ली, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्मित कमेटी एवम् एमवी एक्ट के अनुसार कई तरह की पंजीकरण/परमिट कंडीशन के साथ सीएमवीआर के अंतर्गत वाहनों की श्रेणी की अलग पहचान हेतु अलग अलग कलर कोड, एवम् सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गैजट नोटिफिकेशन के अनुसार कई अन्य कंडीशन को पूरा करना होता है।

भारत देश की जनता को सार्वजनिक वाहन सेवा सुखद, सुरक्षित उपलब्ध हो इसके लिए समय समय पर सुरक्षा के प्रति नई कंडीशन लागू करने हेतु सभी राज्यों के परिवहन विभाग में एसटीएबोर्ड का गठन अनिवार्य किया गया है।

*पिछले 9 सालों में दिल्ली भारत देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा राज्य की जनता की सुरक्षा को दरकिनार कर

1. तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारी लगा दिए जिन्हें वाहनों से संबंधित जानकारी के नाम पर अ ब स का भी अता- पता तक नहीं है और वह अधिकारी दिल्ली में वाहनों की अल्टरेशन, फ्यूल मोड बदलाव के आदेशों के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस तक जारी कर रहे हैं।

2. दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि में शामिल होने वाले सवारी सेवा वाहनों के पंजीकरण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन जिसके अंदर वाहन पंजीकरण करवाने वाले मालिक/ कंपनी का पते के साथ करेक्टर रिपोर्ट होना आवश्यक है।

3. दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि में पंजीकरण सिर्फ दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति और दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि करने वाली कम्पनी के नाम ही हो सकता है।

4. दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि में शामिल होने वाले वाहन का फ्यूल मोड, कलर कोड एवम्-श्रेणी के प्रति लागू अन्य सभी कंडीशन पूरी होने के बाद ही संभव है।

आपके याद ही होगा दिल्ली में घटित सबसे बड़ी दुर्घटना जिसने दिल्ली को शर्मसार कर दिया था और वह था **"निर्भया कांड"** जो सिर्फ इसी कारण हुआ था की बाहरी राज्य में रहने वाले व्यक्ति ने दिल्ली का गलत पता देकर सार्वजनिक सवारी सेवा का वाहन अपने नाम पंजीकृत करवा रखा था और जब व्यवसायिक वाहन खास तौर से सार्वजनिक सवारी सेवा में प्रयोग होने वाले का पंजीकरण वाहन डीलर/ निर्माता को दे दिया जाता है तो क्या वह अपने वाहनों को बेचने पर ध्यान देंगे या जनता की सुरक्षा के लिए अनिवार्य वाहन मालिक के सही प्रमाण?

दिल्ली परिवहन आयुक्त क्यों दिल्ली की जनता की सुरक्षा को ताक पर रखकर व्यवसायिक गतिविधि में शामिल होने वाले वाहनों का पंजीकरण वाहन निर्माता/ वाहन डीलर को देना चाहते है यह तो वह ही बेहतर जानते होंगे पर भारत के संविधान के अनुसार जनता की सुरक्षा को ताक पर लगाने का हक और ताकत शायद किसी को भी प्रदान नहीं की गई है।

दिल्ली की हवा में जहर: थर्मल पावर प्लांट निकले सबसे बड़े दोषी, पराली जलाने का मिथक टूटा

इशिका, मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

नई दिल्ली। दिल्ली की जहरीली हवा का संकट हर साल गहराता जा रहा है, लेकिन इस बार एक बड़ी सच्चाई सामने आई है। लंबे समय से गाड़ियों और पराली जलाने को दोषी ठहराया जाता रहा है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि असली जिम्मेदार थर्मल पावर प्लांट हैं। एक फिनलैंड बेस्ड स्वतंत्र थिंक टैंक ***सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए)** की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है।

थर्मल पावर प्लांट: सबसे बड़े प्रदूषक

1. 16 गुना ज्यादा प्रदूषण:

रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर में स्थित थर्मल पावर प्लांट हर साल 281 किलो टन सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जित करते हैं। इसकी तुलना में पराली जलाने से केवल 17.8 किलो टन SO_2 का उत्सर्जन होता है।

2. *पराली जलाने का मिथक टूटा:*

पराली को प्रदूषण का मुख्य कारण बताकर किसानों को दोषी ठहराया जाता रहा है। लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि थर्मल पावर प्लांट पराली से 16 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।

3. *वायु गुणवत्ता पर गहरा असर:*

दिल्ली और एनसीआर में इन प्लांट्स से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक कणों को बढ़ा रहा है, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।

* अदालत का सख्त रुख*

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इस गंभीर मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और सख्त रुख अपनाया है।

- *नोटिस जारी:*

एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

- *वायु अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन:*

कोर्ट ने कहा है कि यह मामला वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्पष्ट उल्लंघन है।

मौसम भी बना रहा है संकट गहरा**

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट के पीछे मौसम की भूमिका भी अहम है।

1. ठंडी हवाएं और रुकी हुई हवा:

गिरते तापमान और धीमी हवाओं के चलते प्रदूषक तत्व हवा में फंसे रहते हैं, जिन्हें स्कोल्ड एयर ट्रैपिंग कहा जाता है।

2. धूल और धुआं:

हवा की गति कम होने से थर्मल पावर प्लांट और अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषक लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब होती है।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल

इस रिपोर्ट ने सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

- थर्मल पावर प्लांट्स पर कार्रवाई क्यों नहीं?

गाड़ियों और पराली को बार-बार दोषी ठहराना आसान है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स जैसे बड़े प्रदूषकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?

- किसानों को बलि का बकरा बनाना:

पराली जलाने पर जुर्माना लगाना और किसानों को प्रदूषण का मुख्य कारण बताना सरकार की एकतरफा नीति को दर्शाता है।

समाधान की तलाश में देरी क्यों?

एनसीआर में प्रदूषण का संकट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके समाधान में देरी हो रही है।

- प्लांट्स को अपग्रेड क्यों नहीं किया गया?

थर्मल पावर प्लांट्स में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने की बात लंबे समय से हो रही है, लेकिन इसे लागू करने में सुस्ती बरती जा रही है।

- सरकार की प्राथमिकता पर सवाल:

जब इतने बड़े पैमाने पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पावर प्लांट्स पर कार्रवाई नहीं होती, तो यह सवाल उठता है कि क्या सरकार की प्राथमिकता वाकई पर्यावरण बचाना है?

जनता पर असर

दिल्ली और एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है, और इसका सीधा असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

- बीमारियों का खतरा:

सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों की बीमारियां, और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।

- जीवन स्तर पर प्रभाव:

दिल्ली में रहने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) पर इसका बुरा असर पड़ रहा है।

आगे का रास्ता

दिल्ली और एनसीआर की हवा को साफ करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।

1. थर्मल पावर प्लांट्स पर सख्त कार्रवाई:

इन प्लांट्स में प्रदूषण नियंत्रण तकनीक लगाई जानी चाहिए और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए।

2. पराली जलाने की समस्या का समाधान:

किसानों को वैकल्पिक साधन मुहैया कराना चाहिए ताकि वे पराली जलाने से बच सकें।

3. जनजागरूकता:

आम लोगों को प्रदूषण के खतरों और इसे कम करने के उपायों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

दिल्ली की हवा हर गुजरते साल के साथ और जहरीली होती जा रही है। रिपोर्ट में थर्मल पावर प्लांट्स को सबसे बड़ा दोषी बताया गया है, लेकिन सरकार और प्रशासन की निष्क्रियता इसे और गंभीर बना रही है। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले समय में यह संकट और भयावह हो सकता है।

इलैक्ट्रिक व्हीकल का ई-कचरा निपटान एक बड़ी चुनौती (सम-सामयिक मुद्दा)

पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में एक बहुत ही गंभीर और बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए या यूं कहें कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार पिछले कुछ समय से देश में इलेक्ट्रोनिक वाहन (ईवी) को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने 'ईवी तकनीक' में भारी निवेश किया है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, और इसका बहुत बड़ा कारण पेट्रोल की कीमतों की स्थिति, तथा वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चिंताएं हैं। आज आम व खास दोनों का ही रूझान भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद की ओर लगातार बढ़ा है, क्यों कि एक तो इन वाहनों पर सब्सिडी मिल जाती है, दूसरे छोटे वाहनों का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है या इनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2022 में भारत के आधे से अधिक तिपहिया पंजीकरण इलेक्ट्रिक वाहन थे, जो ईवी अपनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है। वर्तमान में हमारी सरकारें देश में बड़े शहरों में ई-चार्जिंग स्टेशनों को भी बढ़ावा देने की ध्यान दे रही है और अनेक शहरों में तो इनकी शुरूआत भी हो चुकी है। बहरहाल, यह ठीक है कि इलैक्ट्रिक वाहनों में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने और जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला कर सकने की अभूतपूर्व क्षमताएं है और ये तेल आयात को भी कम करने में मदद करते हैं और ऊर्जा विविधता लाने में भी योगदान करते हैं, कांपैक्ट डिजाइन के कारण शहरों में भीड़भाड़ कम करने में भी मदद करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इलैक्ट्रिक वाहनों से हमारे पर्यावरण,हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर कहीं न कहीं विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में आज इतनी अधिक संख्या में देश की मांग के अनुरूप ईवी बैटरी उत्पादन से हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।इससे धरती पर जैव-विविधता की हानि, वायु प्रदूषण और मीठे पानी की आपूर्ति में कमी जैसे प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहे हैं।

एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक नई कारों की बिक्री का 52% हिस्सा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा। इलैक्ट्रिक वाहन बड़ी बैटरियों से चलते हैं, और मुख्य चिन्ता यह है कि चार्जिंग के अलावा, इलैक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) उत्पादन से भी कार्बन उत्सर्जन होता है। आंकड़े बताते हैं कि 43 किलोवाट-घंटे की औसत क्षमता के साथ, केवल एक ईवी बैटरी का उत्पादन करने से लगभग उतना ही कार्बन उत्सर्जन होता है जितना कि एक गैसोलीन कार को लगभग 50,000 मील चलाने से होता है। बैटरियों में पाये जाने वाले लिथियम और निकल भी कार्बन पदचिह्न में योगदान करते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि बैटरी निर्माण प्रक्रियाओं का पर्यावरण पर काफी प्रभाव पड़ता है। दरअसल, ईवी की लिथियम-आयन बैटरी के घटकों को खनन करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों को आसानी से रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, जो दुनिया भर में बढ़ती ई-कचरे की समस्या को बढ़ाता है। अतः कहना ग़लत नहीं होगा कि इलैक्ट्रिक वाहनों में भी अपशिष्ट की समस्या एक बड़ी समस्या है, जो मनुष्य के लिए एक चुनौती है। यह ठीक है कि लिथियम-आयन बैटरियां हमारी अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनका अपशिष्ट इतना होता है कि जीवाश्म ईंधन पर उनका कोई विशेष फायदा नजर नहीं आता है। एक आंकड़े के अनुसार लिथियम-आयन अपशिष्ट की यह संख्या वर्ष 2030 तक लगभग 3.2 मिलियन टन तक पहुँच जाने की संभावनाएं हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक ई-कचरा मॉनिटर 2020 के अनुसार, भारत, जो पहले से ही एक बड़ी ई-कचरे की समस्या से जूझ रहा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कचरा उत्पादक है। सरकार की इलैक्ट्रिक वाहनों की पहल पर्यावरण के लिहाज से ठीक है लेकिन इलैक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों का अनुचित तरीके से निपटान भारत में ई-कचरे की बढ़ती समस्या में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जिससे ईवी(इलैक्ट्रिक व्हीकल) क्रांति के साथ-साथ पर्यावरणीय चिंताएँ भी बढ़ सकती हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि हम ई-कचरे के निपटान की दिशा में भी उचित एवं सकारात्मक कदम उठायें।

(लेख पूर्णतया मौलिक और अप्रकाशित है।)

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

खतरनाक होता बायोमेडिकल वेस्ट

स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कुल अपशिष्ट में से लगभग 85% सामान्य, गैर-खतरनाक अपशिष्ट है। शेष 15% को खतरनाक सामग्री माना जाता है जो संक्रामक, विषाक्त, कैंसरकारी, ज्वलनशील, संक्षारक, प्रतिक्रियाशील, विस्फोटक या रेडियोधर्मी हो सकता है। हर साल दुनिया भर में अनुमानित 16 बिलियन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन सभी सुइयों और सिरिंजों का उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों को खुले में जलाने और कम तापमान पर जलाने से, कुछ परिस्थितियों में, डाइऑक्सिन, फ़्यूरान और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन हो सकता है।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

स्वास्थ्य सेवा गतिविधियाँ स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं और उसे बहाल करती हैं तथा जीवन बचाती हैं। लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट और उप-उत्पादों के बारे में क्या? स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कुल अपशिष्ट में से लगभग 85% सामान्य, गैर-खतरनाक अपशिष्ट है जो घरेलू अपशिष्ट के बराबर है। शेष 15% को खतरनाक सामग्री माना जाता है जो संक्रामक, रासायनिक या रेडियोधर्मी हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उपाय ऐसे अपशिष्टों से होने वाले प्रतिकूल स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों को रोक सकते हैं, जिसमें रासायनिक या जैविक खतरों का अनपेक्षित उत्सर्जन शामिल है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों में संभावित रूप से हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं जो अस्पताल के रोगियों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता को संक्रमित कर सकते हैं। अन्य संभावित खतरों में दवा प्रतिरोधी सूक्ष्मजीव शामिल हो सकते हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं से पर्यावरण में फैलते हैं। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट और उप-उत्पादों से जुड़े प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों में तीक्ष्ण वस्तुओं से लगी चोटें भी शामिल हैं; स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों के संचालन या भस्मीकरण के दौरान आस-पास के वातावरण में छोड़े जाने वाले दवा उत्पादों, विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स और साइटोटॉक्सिक दवाओं और पारा या डाइऑक्सिन जैसे पदार्थों के संपर्क में आना; कीटाणुशोधन, बंध्यीकरण या अपशिष्ट उपचार गतिविधियों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली रासायनिक जलन; चिकित्सा अपशिष्ट भस्मीकरण के दौरान कण पदार्थ के निकलने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वायु प्रदूषण; खुले में जलने और चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक के संचालन के साथ होने वाली तापीय चोटें; विकिरण जलन; और दवा अपशिष्टों के असुरक्षित भंडारण, उपचार और निपटान के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध का प्रसार। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट सेवाओं के लिए कई कारण मौजूद हैं। इनमें सीमित कानूनी ढाँचे (जैसे, नीतियाँ, विनियमन, दिशा-निर्देश), स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट से सम्बंधित स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता की कमी, उचित अपशिष्ट प्रबंधन में अपर्याप्त प्रशिक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान प्रणालियों की अनुपस्थिति, अपर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन और कम प्राथमिकता शामिल हैं। कई देशों में या तो उचित नियम नहीं हैं या वे उनकी निगरानी और प्रवर्तन नहीं करते हैं।

दुनिया भर में, हर साल अनुमानित 16 बिलियन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सभी सुइयों और सिरिंजों का सुरक्षित तरीके से निपटान नहीं किया जाता है, जिससे चोट और संक्रमण का जोखिम और दोबारा इस्तेमाल के अवसर पैदा होते हैं। हाल के वर्षों में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दूषित सुइयों और सिरिंजों से इंजेक्शन लगाने में काफ़ी कमी आई है, आंशिक रूप से इंजेक्शन उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल को कम करने के प्रयासों के कारण। इस प्रगति के बावजूद, असुरक्षित इंजेक्शन अभी भी 33, 800 नए एचआईवी संक्रमण, 1.7 मिलियन हेपेटाइटिस बी संक्रमण और 315, 000 हेपेटाइटिस-सी संक्रमण के लिए ज़िम्मेदार थे। संक्रमित स्रोत रोगी पर इस्तेमाल की गई सुई से एक व्यक्ति को सुई लगने से चोट लगने का अनुभव होने पर उसे एचबीवी, एचसीवी और एचआईवी से संक्रमित होने का क्रमशः 30%, 1.8% और 0.3% जोखिम होता है। अपशिष्ट निपटान स्थलों पर सफ़ाई करने और स्वास्थ्य सुविधाओं से खतरनाक अपशिष्ट को संभालने और मैन्युअल रूप से छांटने के दौरान अतिरिक्त खतरे उत्पन्न होते हैं। ये प्रथाएँ दुनिया के कई क्षेत्रों में आम हैं, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। अपशिष्ट संचालकों को सुई चुभने की चोट लगने और विषैले या संक्रामक पदार्थों के संपर्क में आने का तत्काल जोखिम होता है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट का उपचार और निपटान पर्यावरण में रोगजनकों और विषैले प्रदूषकों के निकलने के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।

लैंडफिल में अनुपचारित स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों के निपटान से पीने, सतह और भूजल का संदूषण हो सकता है, अगर उन लैंडफिल का निर्माण ठीक से नहीं किया गया है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों को कम से कम करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे उस अपशिष्ट की मात्रा में काफ़ी कमी आएगी जिसे संभालने और उपचारित करने की आवश्यकता है। अपशिष्ट न्यूनीकरण क्रियाओं में हरित खरीद और ऐसे उत्पादों का चयन करना शामिल है जहाँ शिपिंग कम से कम हो और कम और पारिस्थितिक पैकेजिंग हो, सुरक्षित और व्यवहार्य होने पर पुनः प्रयोज्य उत्पादों पर स्विच करना, केवल प्रलेखित आवश्यकता के आधार पर फार्मास्यूटिकल्स का ऑर्डर देना / प्राप्त करना और प्लास्टिक, काग़ज़ और कार्डबोर्ड सहित सामान्य वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना शामिल है। रासायनिक कीटाणुनाशकों के साथ स्वास्थ्य सेवा अपशिष्टों के उपचार के परिणामस्वरूप पर्यावरण में रासायनिक पदार्थ निकल सकते हैं यदि उन पदार्थों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संभाला, संग्रहीत और निपटाया नहीं जाता है।

स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अधिक ध्यान और परिश्रम की आवश्यकता होती है, ताकि खराब अभ्यास से जुड़े प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों से बचा जा सके, जिसमें संक्रामक एजेंटों और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना भी शामिल है। स्वास्थ्य सेवा अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के प्रमुख तत्व हैं उन प्रथाओं को बढ़ावा देना जो उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को कम करते हैं और उचित अपशिष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करते हैं; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के अंतिम उद्देश्य के साथ अपशिष्ट पृथक्करण, विनाश और निपटान प्रथाओं में क्रमिक रूप से सुधार करने के लिए मज़बूत निगरानी और विनियमन के साथ-साथ रणनीति और प्रणाली विकसित करना; जहाँ संभव हो, चिकित्सा अपशिष्ट भस्मीकरण की तुलना में खतरनाक स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल उपचार (उदाहरण के लिए, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, आंतरिक मिश्रण के साथ एकीकृत भाप उपचार और रासायनिक उपचार) का पक्ष लेना; एक व्यापक प्रणाली का निर्माण, जिम्मेदारियों, संसाधन आवंटन, तथा अपशिष्ट को एकत्रित करने, संभालने, भंडारण करने, परिवहन करने, उपचारित करने या निपटाने के दौरान लोगों को खतरों से बचाने के लिए सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन विकल्पों का चयन करना। सार्वभौमिक, दीर्घकालिक सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और समर्थन की आवश्यकता है, हालांकि स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्यवाही की जा सकती है।

हथियार (कहानी)

विकास बारहवीं कक्षा का छात्र था और आज उसका बारहवीं का लास्ट एक्जाम था। इसलिए सुबह से ही विकास अपनी कक्षा के अन्य सभी सहपाठियों की तरह बहुत ही खुशमिजाज नज़र रहा था, क्यों कि रिजल्ट आने के बाद वह कालेज में हो जाएगा। अपना बारहवीं कक्षा का लास्ट एक्जाम देकर विकास शाम को खुशी से चहकते हुए अपने घर वापस आ गया। उसकी बारहवीं की परीक्षा आज खत्म हो चुकी थी और अब उसे कुछ दिनों तक के लिए कोई भी चिंता नहीं थी। अब वह खेलकूद सकता था, मौज-मस्ती कर सकता था, दोस्तों संग फन-टाइम एंजॉय कर सकता था। उस दिन विकास अपनी मम्मा और डैड के साथ शहर के एक होटल में डिनर करने गया और खूब एंजॉय किया। अगले दिन, सुबह-सुबह विकास की मम्मा कादम्बिनी घर की साफ-सफाई में जुटी में थी। घर की साफ-सफाई करते हुए वह विकास के कमरे में पहुंचीं, विकास का कमरा एक्जाम के कारण काफी दिनों से बहुत ही अस्त-व्यस्त था। विकास को कमरा ठीक से जंचाने/कमरे को सुव्यवस्थित, साफ व स्वच्छ रखने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। उसकी मम्मा कादम्बिनी भी सिलाई के काम के कारण घर में काफी व्यस्त थी। आज विकास के एक्जाम खत्म होने के बाद उसने विकास के कमरे की साफ-सफाई के लिए थोड़ा समय निकाल लिया था। कादम्बिनी ने देखा कि कहीं टेबल पर विकास की बारहवीं कक्षा की पुस्तकें इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं, तो कहीं पर नोटबुक्स तो कहीं पुराने पेन, पेंसिल ,शार्पनर, कम्पास, प्रोट्रैक्टर, कैलकुलेटर तो कहीं स्कूल बैग तो कहीं उसके स्कूली जूते और वर्दी। विकास का सामान कमरे में यूं बिखरा देखकर विकास की मम्मा कादम्बिनी ने विकास से कहा-' बेटा विकास ! ज़रा इधर तो आओ। देखो बेटा, अब तुम्हारी बारहवीं की परीक्षाएं भी खत्म हो गई है, और बारहवीं के रिजल्ट के बाद तुम्हें कालेज में एडमिशन लेना है। पुरानी किताबें, स्टेशनरी का सामान और तुम्हारा स्कूल बैग, जूते और वर्दी अब तुम्हारे तो काम में आने से रहे। ऐसे करेंगे ये सारा सामान(स्टेशनरी आइटम्स,जूते वगैरह) हम कबाड़ वाले को क्यों न दे दें ? कबाड़ बेचकर इनसे जो चार रूपए आयेंगे, उन पैसों में कुछ और पैसे मिलाकर तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड तुम्हारी नयी कक्षा के लिए किताबें,बैग, स्टेशनरी जूते आदि खरीद लेंगे। यूं ही पिछले काफी समय से तुम्हारा कमरा आलतू-फालतू के सामान से अटा पड़ा है और इसकी वज़ह से मैं ठीक से तुम्हारे कमरे की साफ़- सफाई भी नहीं कर पाती हूं।' अपनी मम्मा कादम्बिनी की बात सुनकर विकास ने प्रतिक्रिया में बस यही कहा कि-' मम्मा अभी तो मैं अपने खास दोस्त और सहपाठी साहिल के साथ किसी काम से बाहर स्टेडियम की तरफ जा रहा हूं। मम्मा आप मुझे माफ़ करना इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूं, वो क्या है कि अभी-अभी साहिल का मेरे पास स्टेडियम की ओर जाने के लिए फोन आया था। कल मैं आपको बताऊंगा कि हमें किताबों, स्टेशनरी आइटम्स, बैग, वर्दी आदि का क्या करना है और क्या नहीं। बस मम्मा आज-आज की ही तो बात है। आज-आज आप थोड़ा-सा सब्र और बनाए रखें। इतने दिनों तक भी तो आप सब्र बनाए हुए थीं। एक और दिन में क्या फर्क पड़ता है मम्मा ?' और ऐसा कहते हुए विकास साहिल के साथ फुर्ती से घर से बाहर स्टेडियम की ओर निकल गया। थोड़ी देर में साहिल और विकास अब स्टेडियम की ओर रास्ते में थे। रास्ते में उन्होंने झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करने वाले लोगों को देखा कि किस प्रकार से वे ग़रीबी और कम संसाधनों में अपना जीवन काटने को मजबूर थे। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे स्कूल जाने से वंचित थे, क्यों कि उनके पास बच्चों को पढ़ने-पढ़ाने के लिए उतने संसाधन मौजूद नहीं थे। उस दिन विकास मन ही मन सोच रहा था कि वह ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए अपने जीवन में जितना वह कर सकता है, जरूर करेगा। कुछ काम के बाद, कुछ समय बाद साहिल और विकास दोनों स्टेडियम से अपने-अपने घर लौट आए। अब शाम हो चली थी और विकास जब अपने घर वापस पहुंचा तो उसकी मम्मी कादम्बिनी, उसके पापा सुमित डायनिंग टेबल पर डिनर के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। विकास हाथ-पांव धोकर अब डिनर टेबल पर था। डिनर करते वक्त विकास के डैड सुमित ने विकास से कहा-' बेटा ! कल तुम अपने कमरे को अच्छे से सैट कर लो, अब तुम्हारी छुट्टियां भी हो गई है, तुम्हें घर के छोटे छोटे काम में हाथ बंटाकर तुम्हारी मम्मा की सहायता करनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। तुम्हारी मम्मा तो सिलाई मशीन पर हमेशा व्यस्त रहती है। बेटा विकास ! तुम्हारी कापी-किताबें अब यूं ही घर में व्यर्थ पड़ी है, अब हमारे घर में ये किसी काम की भी नहीं है। तुम्हारे कोई छोटा भाई भी नहीं है,जो तुम्हारी किताबों को पढ़ लेगा। अच्छा रहेगा बेटा यदि हम तुम्हारी पुरानी कापी-किताबें किसी कबाड़ वाले को बेचकर तुम्हारे नयी कक्षा में जाने की तैयारी करें।' विकास डिनर ले रहा था और खाना खाते-खाते उसने अपने डैड की बातें सुनकर जैसे हामी में हल्का सा अपने सिर को हिलाया। कादम्बिनी उसकी(विकास) सहमति से जैसे हल्की सी अजीब सी नज़र आ रही थी, हालांकि स्वयं उसने किताबों को कबाड़ में देने की बात कही थी, लेकिन क्या सोचकर यह शायद स्वयं उसे(कादम्बिनी) भी पता नहीं था, लेकिन विकास की हामी भरने पर वह बोली कुछ भी नहीं। सभी ने डिनर ले लिया था और सभी अपने-अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। विकास भी अपने बिस्तर पर था। आज उसे नींद नहीं आ रही थी। एक्जाम के दिनों में बहुत नींद आती थी लेकिन आज उसका मन कहीं जैसे भावनाओं में डुबकियां लगा रहा था, वह उनमुना सा था। बिस्तर पर लेटा लेटा आज वह सोच रहा था कि कबाड़ वाले की बजाय यदि वह अपनी किताबों को किसी गरीब बच्चे को दे दें, तो उसका किताबों का खर्च तो कम से कम बच ही जाएगा। यदि कोई गरीब परिवार का बच्चा भी(बारहवीं कक्षा का) नहीं मिलता है तो वह अपनी किताबों को शहर के सार्वजनिक पुस्तकालय में या किसी अनाथालय में देना अधिक पसंद करेगा। विकास यह सोच रहा था कि आज भी इस देश में लाखों ऐसे बच्चे है, जिनके पास पढ़ाई के पर्याप्त साधन नहीं है।किताबों को लंबे समय तक घर में यूं ही रखे रहने या इन्हें कुछ पैसों के लिए कबाड़ वाले को देने से बेहतर यह है कि वह अपने किसी दोस्त या नज़दीकी या किसी गरीब परिवार के बच्चे को इन्हें गिफ्ट/दान कर दे। विकास यह सोच रहा था कि इससे ना सिर्फ उसकी किताबों का सदुपयोग ही हो पाएगा, बल्कि इससे किसी गरीब बच्चे का भविष्य भी बेहतर हो सकता है। ऐसा सोचते-सोचते न जाने कब विकास को नींद आ गई थी। अगले दिन सुबह-सुबह गली में कबाड़ ख़रीदने वाला जोर जोर से कबाड़ के लिए टेर पर टेर लगा रहा था। कादम्बिनी ने कबाड़ वाले की टेर सुनकर विकास को आवाज लगाई, जो अभी भी सोया हुआ था। कादम्बिनी ने कहा-' बेटा जल्दी उठो, तुम्हारे कमरे का कबाड़ आज साफ नहीं करना क्या ? तुम्हारे पापा ने कल तुम्हें क्या कहा था ? तुम्हें याद है ना। देखो ! बाहर गली में कबाड़ वाला आया है। जल्दी से अपनी किताबों, स्टेशनरी आइटम्स वाले सारे कबाड़ को अपने कमरे से बाहर निकालो। उठो बेटा !' विकास अपनी मम्मा कादम्बिनी की आवाज सुनकर थोड़ी देर बाद अपने कमरे से बाहर आया और उसने अपनी मां से कहा-' मां ! ये जो मेरी किताबें है ना, ये किसी की जिंदगी और तकदीर दोनों बदल सकतीं है। हम महज़ कुछ पैसों के लालच और स्वार्थ के लिए इन्हें कबाड़ वाले को कतई नहीं बेचेंगे। मम्मा ! दरअसल, मैं यह चाहता हूं कि हम इन्हें गरीब परिवार के किसी बच्चे को ये सब दान करें। इससे हमें आत्मिक शांति और खुशी मिलेगी।' कादम्बिनी ने विकास की बातें सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया। शायद वह भी यही चाहती थी। भले ही उसने पहले एक दिन अनमने मन से किताबों को कबाड़ वाले को बेचने के लिए विकास को कह दिया था। आज उसकी(कादम्बिनी) आंखों में ख़ुशी के आंसू छलक उठे थे, क्यों कि स्वयं कादम्बिनी का परिवार बहुत बड़ा था। दरअसल कादम्बिनी के पांच बहनें और दो भाई थे, और पिता एक फैक्टरी में काम करते थे। ऐसे में उसके परिवार के सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पिताजी के पास पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे। फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह से घर का गुज़ारा बमुश्किल चलता था।

आज यकायक अपने बेटे विकास के मुख से किताबों को गरीब बच्चे को डोनेट किए जाने की बात सुनकर कादम्बिनी को स्वयं के परिवार के आर्थिक हालात याद आ गये थे कि किस प्रकार से उसके पिताजी ने दान की गई किताबों से ही पूरे परिवार को शिक्षित किया था और केवल शिक्षा के बल पर अपनी पांचों बेटियों की शादी अच्छे घरों में की थी। कादम्बिनी अपने बेटे विकास को बांहों में भरे लगातार यह सोचती चली जा रही थी कि -'शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है।'

(कहानी पूर्णतया मौलिक और अप्रकाशित है।)

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

खुशखबरी ! दिल्ली-हरियाणा को जोड़ेगा मेट्रो का नया कॉरिडोर, पीएम मोदी ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-हरियाणा के बीच बनने वाले रिठाला-कुंडली-नाथूपुर मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। यह कॉरिडोर दिल्ली के रिठाला से शुरू होकर हरियाणा के कुंडली स्थित नाथूपुर तक जाएगा। 26.463 किलोमीटर लंबा यह मेट्रो कॉरिडोर 6230 करोड़ की लागत से चार वर्ष में बनकर तैयार होगा। इससे दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क की कनेक्टिविटी और आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।

नई दिल्ली। फेज चार में प्रस्तावित रिठाला-कुंडली-नाथूपुर मेट्रो कॉरिडोर (Rithala-Kundli-Nathupur Metro Corridor) को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इससे इस कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

दिल्ली के रिठाला, बवाना व नरेला से होते हुए हरियाणा के कुंडली स्थित नाथूपुर तक इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। 26.463 किलोमीटर लंबा यह मेट्रो कॉरिडोर 6230 करोड़ की लागत से चार वर्ष में बनकर तैयार होगा। इससे दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क की कनेक्टिविटी व आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।

हरियाणा के कुंडली-नाथूपुर तक सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध

इससे एनसीआर के लोगों बड़ी राहत मिलेगी। यह कॉरिडोर वर्तमान रेड लाइन (रिठाला-न्यू बस अड्डा गाजियाबाद) की विस्तार परियोजना है। इसलिए यह कॉरिडोर बनकर तैयार होने पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहीद स्थल से हरियाणा के कुंडली-नाथूपुर तक सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी।

इसलिए रेड लाइन दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर होगा जो तीन राज्यों के शहरों को मेट्रो नेटवर्क से सीधा जोड़ेगी। यह कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा और इस 21 मेट्रो स्टेशन होंगे। यह मेट्रो का चौथा कॉरिडोर होगा जो हरियाणा को दिल्ली से जोड़ेगा।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) इसका निर्माण कराया है। डीएमआरसी में केंद्र व दिल्ली सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। फेज चार में 65.202 किलोमीटर लंबाई के तीन कारिडोर निर्माणाधीन हैं। जिसमें जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कारिडोर, मौजपुर-मजलिस पार्क और तुगलकाबाद-एरोसिटी कारिडोर शामिल हैं। इन तीनों कारिडोर पर 45 मेट्रो स्टेशन होंगे।

डीएमआरसी के अनुसार इन तीनों कारिडोर का अब तक 56 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मार्च 2026 तक यह तीनों कारिडोर बनकर तैयार होंगे। इस वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले 13 मार्च को केंद्र सरकार ने फेज चार के दो अन्य कारिडोर को स्वीकृति दी थी।

जिसमें इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर शामिल है। इन दोनों कॉरिडोर की लंबाई 20.762 किलोमीटर होगी। इन दोनों कॉरिडोर निर्माण के लिए अभी तक टेंडर नहीं हो पाया है। डीएमआरसी का कहना है कि टेंडर जारी करने की तैयारियां चल रही हैं।

रिठाला-कुंडली मेट्रो लाइन फेज चार का छठा कॉरिडोर है, जिसे अब केंद्र की स्वीकृति मिल गई है। इस कॉरिडोर का 23.737 किलोमीटर हिस्सा व 19 स्टेशन दिल्ली में और 2.726 किलोमीटर हिस्सा व दो स्टेशन हरियाणा में होंगे। इस कॉरिडोर का निर्माण होने पर रोहिणी के कई स्टेक्टरों, बवाना, उप नगरी नरेला से भी आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। इससे उप नगरी नरेला के विकास को भी रफ्तार मिलेगी।

मौजूदा समय में एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क 392 किलोमीटर और 288 मेट्रो स्टेशन हैं। दिल्ली में प्रतिदिन 64 लाख यात्राएं यात्री करते हैं। पिछले माह 18 नवंबर को रिकार्ड 78.67 लाख यात्राएं यात्रियों ने की थी।

रिठाला-कुंडली मेट्रो लाइन को स्वीकृति मिलने के बाद अब फेज चार में कुछ छह मेट्रो कॉरिडोर बनेंगे, जिसकी लंबाई 112.426 किलोमीटर व 84 स्टेशन होंगे। इसलिए फेज चार की परियोजना पूरी होने पर एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क करीब 504 किलोमीटर हो जाएगी।

13 मार्च को स्वीकृत फेज चार के दो मेट्रो कॉरिडोर

कॉरिडोर	लंबाई	भूमिगत एलिवेटेड	स्टेशनों की संख्या
लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक			
8.385	**0.00**	**8.385**	**08**
इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ	12.377	8.385	11.349
1.028	10		
कुल	20.762	11.349	9.413
18			

फेज चार का स्वीकृत नया कॉरिडोर

कॉरिडोर	लंबाई	भूमिगत एलिवेटेड	स्टेशनों की संख्या

खास सुविधाओं से लैस दिल्ली का पहला दिव्यांग पार्क बनकर तैयार, इस तारीख को हो सकता है उद्घाटन

पूर्वी दिल्ली में दिव्यांगों के लिए बना पहला पार्क गोरख पार्क वार्ड में बनकर तैयार हो गया है। इस पार्क में दिव्यांगों के अनुकूल पैदल पथ रैंप बैठने की जगह वाद्य यंत्र झूले और ओपन जिम आदि लगे हुए हैं। पार्क का उद्घाटन इसी महीने के अंत तक किया जा सकता है।

पूर्वी दिल्ली। यमुनापार का पहला दिव्यांग पार्क गोरख पार्क वार्ड में लोनी रोड स्थित दो एकड़ भूखंड पर बनकर तैयार हो गया है। इस माह के अंत तक इसे लोगों को समर्पित किया जा सकता है।

नगर निगम ने एक करोड़ रुपये की लागत से इसे बनाया है। इसे दिव्यांगों के अनुकूल बनाया गया है, ताकि उनको पार्क में घूमने-फिरने और खेलकूद में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सामान्य पार्कों में दिव्यांगों को परेशानी होती है। न ही पैदल पथ पर वह सुगमता से चल पाते हैं, न ही झूले उनके हिसाब से लगे होते हैं। इसे देखते हुए विशेष रूप से उनके लिए निगम के शाहदरा उत्तरी जोन के इलाके में बनाए गए दिव्यांग पार्क

में पैदल पथ पर पीले रंग के स्पर्शीय टाइल्स लगाए गए हैं। व्हीलचेयर पर बैठकर आने वालों के रैंप भी बना है। दो जगह गजीबो यानी झोपड़ी आकार में बैठक भी बनाई है। सुंदरता के लिए फूलों से लेकर सजावटी पौधे लगाए हैं।

दिव्यांग पार्क का पैदल पथ। जागरण

इस पार्क में पीपल के 15 बड़े पेड़ लगे हैं, लैंडस्केपिंग भी की गई है। नगर निगम के उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पार्क तैयार हो गया है। किसी भी वक्त इसका उद्घाटन किया जा सकता है, लेकिन तारीख निर्धारित नहीं हुई है।

सीख सकेंगे वाद्य यंत्र

दिव्यांग बच्चों के मनोरंजन के लिए इस पार्क में पूरी व्यवस्था की है। एक हिस्से में अलग-अलग तरीके के वाद्य यंत्र लगाए हैं। बच्चे इस हिस्से में आकर वाद्य यंत्र बजाना सीख सकते हैं। इन यंत्रों में काजोन ड्रम, बाबेल ड्रम (छोटे व बड़े), पैपिलियो बेल, फ्री चाइम्स, रेनबो सांबा, कांगो शामिल है।

सुरक्षा इंतजामों सिहत लगे झूले

झूलों के बिना किसी पार्क की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में इस पार्क में भी दिव्यांगों के अनुकूल झूले लगाए गए हैं। इनमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, ताकि बच्चे गिरे नहीं। इनमें व्हील चेयर स्विंग, सीटर स्विंग, सीटर स्प्रिंग सी-सा, इंटर एमजीआर झूला लगाया गया है।

इस पार्क में ओपन जिम भी है। उसमें भी उपकरण दिव्यांगों के अनुकूल हैं। अगर दिव्यांग व्हील चेयर पर बैठकर एक्सरसाइज करना चाहेंगे तो आराम से कर सकेंगे।

नई शिक्षा नीति को मिली, केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई।

कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2023) को हरी झंडी दे दी है. 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है. नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं:

Five Years Fundamental
1. Nursery @ 4 Years
2. Jr KG @ 5 Years
3. Sr KG @ 6 Years
4. Std 1st @ 7 Years
5. Std 2nd @ 8 Years

Three Years Preparatory
6. Std 3rd @ 9 Years
7. Std 4th @10 Years
8. Std 5th @11 Years

Three Years Middle
9. Std 6th @ 12 Years
10. Std 7th @ 13 Years
11. Std 8th @ 14 Years

Four Years Secondary
12. Std 9th @ 15 Years
13. Std SSC @ 16 Years
14. Std FYJC @ 17Years

15. STD SYJC @18 Years

खास बातें:

#केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड

★MPhil होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की

■10वीं बोर्ड खत्म.

◆अब 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।

●पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा.

★ 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी. स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा।

■वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी. यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी.।

◆3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है. वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी. 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स एक साल में MA कर सकेंगे.

●MA के छात्र अब सीधे PHD कर सकेंगे.

★स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स. हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा. वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है.

■हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं. सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे. वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे. एक नैशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा. बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं.

●सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम।

धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा मंत्री भारत सरकार

डॉ. अम्बेडकर को 68 वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर याद किया गया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के तत्वावधान में दिल्ली विश्वविद्यालय की उत्तरी परिसर के कला संकाय में शुक्रवार को भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 68 वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों का स्मरण किया गया। बाबा साहेब के 68 वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी स्मृति में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आर्यभट्ट कॉलेज में प्रोफेसर के.पी. सिंह ने की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता फोरम के चेयरमैन प्रोफेसर हंसराज सुमन व मंच संचालन आर.के.सरोज ने किया। कार्यक्रम में डॉ. प्रीतम सिंह, डॉ. सुरेंद्र सिंह, श अविनाश, राज कुमार आदि छात्रों के अलावा बहुत से शोधार्थी भी उपस्थित थे।

संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर हंसराज सुमन ने अपने सम्बोधन में कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर एक सच्चे देशभक्त, राष्ट्रवादी व संविधान निर्माता थे। डॉ.अम्बेडकर न केवल विधि विशेषज्ञ थे बल्कि अर्थशास्त्री, साहित्यकार, पत्रकार, राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ, समाजशास्त्री एवं युग दृष्टा थे। उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें उनका योगदान न रहा हो। वे मात्र संविधान निर्माता ही नहीं थे बल्कि राष्ट्र निर्माता भी थे। राष्ट्र के निर्माण में किए गए उनके कार्यो के मार्ग दर्शन में देश आज भी विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे इकलौते महान नायक हैं जिनकी जन्मस्थली पर लाखों लोग शीश झुकाने और वहाँ की पवित्र धूल को माथे लगाने के लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक का पूरा विधान और संरचना बाबा साहेब के सपनों की ही एक निर्मिति है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे बल्कि सम्पूर्ण विश्व के नेता थे, इसीलिए उन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। उन्होंने बताया कि डॉ.अंबेडकर की जयंती व महापरिनिर्वाण दिवस भारत से बाहर विदेशों में भी उनके अनुयायी स्मरण दिवस के रूप में मनाते है।

> संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर हंसराज सुमन ने अपने सम्बोधन में कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर एक सच्चे देशभक्त, राष्ट्रवादी व संविधान निर्माता थे। डॉ.अम्बेडकर न केवल विधि विशेषज्ञ थे बल्कि अर्थशास्त्री, साहित्यकार, पत्रकार, राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ, समाजशास्त्री एवं युग दृष्टा थे।

प्रोफेसर हंसराज सुमन ने आगे अपने उद्बोधन में सामाजिक समरसता के लिए जीवन समर्पित करने वाले बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्षों एवं उनके द्वारा हासिल उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज दुनिया के लगभग 150 से अधिक देशों में बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें स्मरण किया जाता है। यही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली समझे जाने वाले राष्ट्र अमेरिका और योरोप के कई देशों में उनके अध्ययन से संबंधित पीठ की स्थापनाएं की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने जितना संघर्ष किया उसकी एवज में उस समाज को भी उतना ही प्रयास करना चाहिए अन्यथा पिछड़ापान अधिक बढ़ेगा। हमें बढ़-चढ़ कर उनके विचारों पर अमल करना चाहिए। उन्होंने चर्चा के दौरान आगे कहा कि वे एक जागरूक व्यक्ति थे, वह भारतीय समाज को बहुत आगे ले जाना चाहते थे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर के.पी. सिंह ने कहा कि बाबा साहेब को किसी एक क्षेत्र में सीमित करके नहीं देखा जा सकता है बल्कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सभी देशवासी उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। उन्होंने कहा कि देश की सरकारों ने बाबा साहेब के सम्मान के लिए अनेक कार्य किए हैं जिसमें पूरे देश के गरीबों, पिछड़ों के लिए कार्य योजनाएँ बनाई गई हैं और ऐसे में जहाँ बाबा साहेब का महत्व बढ़ रहा है वहीं देश के कल्याण की दिशा भी स्पष्ट हो रही है। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बाबा साहेब को मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, यहाँ उनके नाम पर चेयर बने व उनके नाम पर अम्बेडकर भवन तथा शोध अध्ययन केंद्र खोलने के लिए विश्वविद्यालय कुलपति से मांग की जा रही है कि अन्य आधुनिक चिंतकों की भांति डॉ.अम्बेडकर के सामाजिक कार्यों और लेखन कार्यों पर भी शोध-कार्य होना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में राजकुमार ने डॉ. अम्बेडकर से संबंधित एक गीत गाया, इस संगोष्ठी को सफल बनाने में प्रसून, प्रदीप कुमार, प्रीतम सिंह, सुरेन्द्र सिंह व घनश्याम भारती आदि छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आप विधायक नरेश बाल्यान की बढ़ीं मुश्किलें, मकोका केस में 13 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा

संगठित अपराध के एक मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह देखते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया कि मकोका के तहत 10 दिन के रिमांड की मांग संबंधी जांच एजेंसी के आवेदन पर जिरह में अधिक समय लगेगा। आज उन्हें 13 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा।

नई दिल्ली। संगठित अपराध मकोका के मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू की एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

एक दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर पुलिस ने नरेश बाल्यान को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया। क्राइम ब्रांच की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए बाल्यान से पूछताछ की जरूरत है।

जबरन वसूली मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए नरेश बाल्यान को बुधवार को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

बृहस्पतिवार को उन्हें पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने 10 दिन के रिमांड के आवदेन को ठुकरा कर जांच एजेंसी को विशेष अदालत के समक्ष पेश करने को कहा था।

विशेष अदालत ने रिमांड आवेदन को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए बाल्यान को एक दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

गुरुवार को एक दिन की रिमांड पर भेजे गए थे बाल्यान

संगठित अपराध के एक मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आज वह पूरी हुई तो मकोका मामले में अदालत ने उन्हें 13 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह देखते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया कि मकोका के तहत 10 दिन के रिमांड की मांग संबंधी जांच एजेंसी के आवेदन पर जिरह में अधिक समय लगेगा। साथ ही अदालत ने मामले में जांच एजेंसी की जिरह के लिए छह दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

'पहले से ही कई केस', दिल्ली चुनाव की तैयारियों के बीच केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका; जानें पूरा मामला

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि पहले से ही कई मामले हैं इसलिए मामले पर पूर्व निर्धारित तारीख पर ही सुनवाई होगी। यह मामला 20 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध है।

नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ठुकरा दिया है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि पहले ही ही अदालत के समक्ष कई मामले हैं, ऐसे में मामले पर पूर्व निर्धारित तारीख पर ही सुनवाई होगी। यह मामला 20 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध है।

केजरीवाल की तरफ से पेश वकील ने की ये मांग

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने ईडी द्वारा दाखिल जवाब की प्रति उपलब्ध कराने का जांच एजेंसी को निर्देश देने का अनुरोध किया। अदालत ने ईडी को प्रति उपल्ब्ध कराने का निर्देश देते हुए आवेदन का निपटारा कर दिया।

इससे पहले 21 नवंबर को हाईकोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। साथ ही मामले पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केजरीवाल ने आरोपित के रूप में नामित करने वाले पूरक पत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

अगली सुनवाई पर इसे किया जाएगा रिकॉर्ड-अदालत

केजरीवाल ने तर्क दिया है कि विशेष न्यायाधीश ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया था कि मंजूरी ली गई है और अगली सुनवाई पर इसे रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

आरोप है कि आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच सिफारिश करने के बाद 17 नवंबर 2021 को लागू की गई नीति को सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में लागू GRAP-4 और GRAP-3 के प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया। जिसके बाद दिल्ली में कई चीजों को खोला गया। जिन पर पिछले कुछ हफ्तों से बैन था।

बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए

सुषमा रानी

नई दिल्ली 6 दिसंबर त्रिलोकपुरी विधानसभा के ब्लॉक 27 स्थित निगम पार्षद कार्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को स्मरण किया गया। मयूर विहार वार्ड नंबर 191 की निगम पार्षद बीना बाल गुहेर पटपड़गंज जिला संयुक्त सचिव एवं कोऑर्डिनेटर श्यामलाल बाल गुहेर के साथ एमसीडी अधिकारियों और स्थानीय निवासियों की उपस्थिति में बाबासाहेब के महान विचारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनके अमूल्य योगदान को स्मरण किया गया।

उनका जीवन हमें समानता, समर्पण और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता रहेगा।

केजरीवाल के शासन मॉडल से प्रभावित पूर्व विधायक सुरेन्द्र पाल सिंह बिट्टू "आप" में शामिल

सुषमा रानी

नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। शुक्रवार को सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वह पहले भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा रह चुके है। वह दो बार विधायक और निगम पार्षद भी रह चुके हैं। ₹आपऱ के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी मुख्यालय में उनको पटका और टोपी पहनाकर ₹आपऱ परिवार की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि एकमात्र आम आदमी पार्टी है, जो आम आदमी और दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। हमें उम्मीद है कि सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू के लंबे राजनीतिक अनुभव का दिल्ली की जनता को फायदा मिलेगा। वहीं, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही आम लोगों के दर्द को समझती है और हर जरूरत मंद की जरूरतों को पूरा करती है।

पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू का आम आदमी पार्टी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गवर्नेंस और दिल्ली में शिक्षा, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार

और बाकी सब कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी जॉइन करने का निर्णय लिया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है, जो आम आदमी के लिए काम करती है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू पहले भी दो बार विधायक रह चुके हैं और निगम पार्षद रह चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके राजनीतिक अनुभव का आम आदमी पार्टी और पूरी दिल्ली की जनता को फायदा मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के लिए और अच्छे काम कर पाएंगे।

आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि आज बहुत खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी की नीतियों और अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस के मॉडल से प्रभावित होकर सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू तिमारपुर विधानसभा से 2002 में निगम पार्षद रहे हैं। उसके बाद वह लगातार दो बार तिमारपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं। वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह जनता के बीच अपनी कार्यशैली और कामों के लिए पहचाने जाते हैं।

वहीं, इस मौके पर सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी, एक आम आदमी के दर्द को समझने वाली पार्टी है। इसलिए इसे आम आदमी पार्टी कहा जाता है। हर छोटे से लेकर बड़े आदमी का दर्द और उसकी जरूरतें को आम आदमी पार्टी समझती है। अरविंद केजरीवाल गरीबों के मसीहा हैं। इसलिए मन में आया कि हम भी उनके साथ साथ कंधे से कंधे से मिलाकर इस राह में आगे बढ़ें, जहां यह पार्टी लोगों का भला करने के लिए काम कर रही है।

सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू एक अनुभवी राजनेता हैं, जो 2003 और 2008 में दो बार तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और 2017 में आम आदमी पार्टी से जुड़े। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने 1977 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और अपना दशकों का अनुभव लेकर आम आदमी पार्टी में आए हैं। ग्राउंड लेवल पर आम जनता से उनका जुड़ाव आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत की संभावनाओं को और बल देगा।बिट्टू आम आदमी पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों और पिछड़ों के लिए पार्टी के कार्यों से प्रभावित हैं।

75 लोगों की गिरफ्तारी से क्या डर गए किसान? दो फाड़ हुए संगठन के कार्यकर्ता; कई दिल्ली कूच के लिए अडिग

किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से किसान संगठन आपस में ही दो फाड़ हो गए हैं। इनमें कुछ किसान दिल्ली कूच के साथ ही गिरफ्तारी देने के पक्ष में है। वहीं कुछ किसान प्रशासन द्वारा दी गई 7 दिन की मोहलत का इंतजार कर रहे हैं। आगे विस्तार से पढ़िए।

ग्रेटर नोएडा। दलित प्रेरणा स्थल और यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद किसान संगठन आगे की रणनीति को लेकर दो धड़ों में बंटते नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल कुछ किसान संगठनों दिल्ली कूच पर अडिग रहने के साथ गिरफ्तारी देने के पक्ष में हैं।

उन्होंने आज यानि शुक्रवार को भी जीरो प्वाइंट से दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है। वहीं अन्य संगठन दलित प्रेरणा स्थल पर प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए सात दिन की मोहलत का इंतजार करने के पक्ष में हैं। किसान संगठनों के अलग-अलग राह पकड़ने से आंदोलन की दिशा बदल सकती है।

संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन कर रहे किसान

दस प्रतिशत आबादी भूखंड, नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ देने और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर 25 नवंबर से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दस किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं।

पुलिस ने 75 किसनों को किया गिरफ्तार

दो दिसंबर को दिल्ली कूच और बुधवार को जीरो प्वाइंट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 75 किसानों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। 112 किसानों को केस दर्ज किया है। किसान संगठनों से कई नेता भूमिगत हैं। वाट्सएप ग्रुप और फेसबुक लाइव के जरिये अपने संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं।

लोगों के बहकावे में आकर कोई कदम नहीं उठाएं

भारतीय किसान यूनियन के पश्चिम उत्तर

प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने शुक्रवार को फेसबुक पर लाइव आकर संगठन कार्यकर्ताओं को से कहा कि अन्य लोगों के बहकावे में आकर कोई कदम नहीं उठाएं। किसान हमेशा से वार्ता के पक्षधर रहे हैं। पहले समस्याओं का हल वार्ता से करने का प्रयास करना चाहिए। किसान इसके लिए हमेशा तैयार रहे हैं।

दिल्ली कूच करेंगे किसान

वहीं, प्रशासन ने वार्ता के लिए सात दिन का समय दिया था, उसका इंतजार करें। अगर वार्ता में कोई ठोस फैसला नहीं होता है तो आगे आंदोलन के लिए तैयार रहें। वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल व अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष एवं भूमिगत चल रहे डा. रूपेश वर्मा ने बृहस्पतिवार को प्रेसनोट जारी कर ऐलान किया था कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे जीरो प्वाइंट पर हजारों किसान एकत्र होकर दिल्ली कूच करेंगे।

किसान प्रशासन की गिरफ्तारी व दमनकारी नीति से डरने वाले नहीं है। गांव-गांव में किसान गिरफ्ती के लिए तैयार बैठे हैं। मोर्चा में शामिल जय जवान जय किसान मोर्चा के प्रवक्ता सुनील फौजी भी भूमिगत हैं। उन्होंने भी बृहस्पतिवार को ऐलान किया था कि शुक्रवार को किसान दलित प्रेरणा स्थल पर दोबारा महापड़ाव के लिए जाएंगे। किसान संगठनों के अलग-अलग रुख से आंदोलन की धार कुंद हो सकती है।

जेल में बंद किसान 16 घंटे बाद रिहा, कारागार से बाहर आते ही लिया ये अहम फैसला

सोमवार से शुरू हुए किसानों के विरोध मार्च को लेकर दिल्ली-नोएडा बॉर्डर की सीमाओं पर सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई है। इसके तहत पुलिस-प्रशासन ने बुधवार को जिला कारागार में बंद संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं को 16 घंटे बाद रिहा कर दिया। जिसके बाद महापंचायत कर रहे सैकड़ों किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

ग्रेटर नोएडा। पुलिस प्रशासन ने बुधवार को जिला कारागार में बंद संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं को 16 घंटे बाद रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद किसान नेता सीधे यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट पहुंचे, वहां महापंचायत कर रहे सैकड़ों किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

किसान नेताओं को कंधे पर बैठाकर कार्यकर्ता मंच पर लेकर पहुंचे। महापंचायत में किसानों ने हुंकार भरी कि अब उन्हें किसी कमेटी पर भरोसा नहीं है। अधिकारियों ने किसानों के साथ धोखा किया है। सात दिन में मुख्य सचिव से वार्ता कराने का आश्वासन देकर किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जो फैसला पहले हो चुका है, सरकार उसे लागू करे।

किसानों को दस प्रतिशत भूखंड, भूमि अधिग्रहण के सभी लाभ देने और हाई पावर कमेटी की किसानों के हक में की गई सिफारिशों को तुरंत लागू करें, इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। जरूरत पड़ी तो दोबारा दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत नहीं पहुंच सके। टप्पल में उन्हें पुलिस प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेस वे पर रोक लिया और अपने साथ ले गए। वहीं, किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल पर फिर से धरना देने का एलान किया है। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर महापड़ाव कर रहे किसान, महिलाओं को पुलिस ने मंगलवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया था। महिलाओं, बुजुर्गों एवं बीमारों को बाद में छोड़ दिया, लेकिन किसान नेताओं समेत 123 किसानों को जेल भेज दिया था। इसके विरोध में किसानों ने बुधवार को यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट पर महापंचायत का एलान किया था। महापंचायत के लिए सुबह से बड़ी संख्या में किसान जीरो प्वाइंट पर पहुंचने लगे। करीब 11 बजे तक अलग-अलग किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों किसान महापंचायत में एकत्र हो गए। पुलिस बल को भी भारी तादाद में तैनात किया गया।

सिविल डिफेंस ने बड़ी धूम धाम से बनाया अपना 62 बा स्थापना दिवस

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा: नागरिक सुरक्षा विभाग के 62 बे स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 7 दिनों से प्रोग्राम विभिन्न स्थानों पर कराए गए जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही 1 दिसंबर 2024 को प्रतिभा की खोज जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन एवं समान्य ज्ञान प्रतियोगिता वार्डन पोस्ट संख्या एक के पोस्ट वार्डन अशोक यादव के द्वारा कराई गई जिसके आज अपर जिला अधिकारी नमामी गंगे राजेश यादव, अपर जिला अधिकारी योगानंद पांडे, सेवा निर्वात उप नियंत्रक जसवंत सिंह, सहायक उप नियंत्रक जितेन्द्र देव सिंह, डिप्टी चीफ वार्डन कल्याण दास अग्रवाल, डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी, डिप्टी डिविजनल वार्डन राजेश कुमार मित्तल, घटना नियंत्रक अधिकारी सचिन अग्रवाल के द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा के जिन वार्डन एवं फायर फाइटर ने साल में जो ड्यूटी दी जाती है उसका प्रशास्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया साथ ही जिला स्तरीय प्रतिभा की खोज समान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 450 बच्चो ने भाग लिया आज नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस के मौके पर दोनों वर्गों में से टॉप 20 बच्चो को पुरस्कार जिला अधिकारी मोहदय के द्वारा दिया गया जिसमें प्रथम परस्कार आचार्य देवेश पांडेय और कुमारी दिव्य दूसरा स्थान साधन, कृष्ण कुमार, दीपक श्रेया, आदि बच्चो को पुरस्कार दिया गया साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा से मुकेश तिवारी, अरविन्द चौधरी, बिक्रम, , शैलेश खण्डेलवाल, रावेंद्र बंसल शुभम कुमार, राजेश कुमार , राम सैनी, गुलशेर, मुकेश शर्मा, प्रमोद शर्मा, नरेश अग्रवाल साहिद पवन प्रकाश यतेंद्र नरेंद्र, राकेश रिंकी जवर, आदि वार्डन स्वयंसेवक ने हिस्सा लिया ।

किसान फिर गिरफ्तार, गांव-गांव तक फैली आक्रोश की चिंगारी

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा पुलिस ने एक बार फिर से 34 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। इससे आंदोलन की चिंगारी गांव-गांव में फैल गई है। किसान 10 प्रतिशत आबादी भूखंड भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ और हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने दो दिसंबर को दिल्ली कूच का प्रयास किया था लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था।

ग्रेटर नोएडा। किसान आंदोलन में बुधवार देर रात बड़ा मोड़ आ गया। पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट के नजदीक रात में धरना दे रहे 34 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ज्यादातर किसान नेता पुलिस गिरफ्तारी से बचकर भूमिगत हो गए।

पुलिस की देर रात में हुई कार्रवाई से आंदोलन की चिंगारी गांव-गांव में फैल गई है। गांवों में किसानों के छोटे-छोटे समूह बैठक कर आगे की रणनीति का इंतजार कर रहे हैं। नेताओं का संदेश मिलते ही किसान एकत्र होकर आंदोलन को आक्रामक मोड़ देंगे।

क्या है किसानों की मांगें?

दस प्रतिशत आबादी भूखंड, भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ देने व हाई पावर कमेटी की किसानों के हक में दी गई सिफारिशों को लागू करने के लिए 25 नवंबर से किसान संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में दस किसान संगठन महापड़ाव कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण पर महापड़ाव के बाद किसानों ने दो दिसंबर को दिल्ली कूच का प्रयास किया था, लेकिन महामाया फ्लाईओवर के नजदीक पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया।

किसानों की मुख्य सचिव से एक सप्ताह में वार्ता का आश्वासन दिया, इसके बाद किसान दलित प्रेरणा स्थल पर महापड़ाव कर धरने पर बैठ गए, लेकिन मंगलवार को पुलिस ने प्रमुख नेताओं समेत 123 किसानों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में बुधवार को किसानों ने यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट पर महापंचायत हुई।

अधिकारियों ने किसानों की मांग पर शाम को करीब चार बजे किसान नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। इसके साथ ही हाई पावर कमेटी की सिफारिश इसी माह लागू कराने और अन्य मांगों को शासन स्तर से निस्तारण करने का आश्वासन दिया। लेकिन किसान जीरो प्वाइंट पर ही रात में धरने पर बैठे रहे। देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुखबीर खलीफा और सोरन प्रधान समेत 34 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इसके बाद अन्य नेता भूमिगत हो गए। उनकी तलाश में पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है। नेताओं ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपने मोबाइल फोन भी बंद कर लिए हैं। गांव-गांव किसान पंचायत कर आगे की रणनीति का संदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 12 बजे किसान एक बार फिर जीरो प्वाइंट पर एकत्र हो सकते हैं।

किसान नेता डॉ. रुपेश वर्मा का कहना है कि पुलिस ने वादा खिलाफी की है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को 4 दिसंबर की रात में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने दमन उत्पीड़न करते हुए अपने ही वादे से मुकरते हुए सुखबीर खलीफा एवं सोरन प्रधान सहित 15-20 किसानों को जेल भेज दिया है।

किसान सभा के जिला महासचिव जगबीर नंबरदार जिला उपाध्यक्ष गवरी मुखिया को अन्य 10 लोगों के साथ रात में ही घर से पकड़ कर जेल भेज दिया है। संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का कहर रात भर जारी रहा। उदल आर्य के घर के गेट को तोड़ते हुए उनकी पत्नी को भी थाने में ले जाकर बिठा दिया। किसान दमन और उत्पीड़न से पीछे हटने वाले नहीं है।

शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नागरिकों का हक है। योगी सरकार ने किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का दमन करने की कोशिश की है। सरकार पूरी तरह पूंजी पति परस्त एवं किसान विरोधी है। किसानों की जमीन पर नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना सिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। उन्हें उनका हक पिछले 50 सालों से नहीं मिला है । उनके विकसित आबादी प्लाट अभी तक नहीं मिले हैं।

प्राधिकरण के अफसर भ्रष्टाचार कर किसान के हिस्से की जमीन को भी खा गए हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 10 परसेंट के प्लाट नहीं दिए गए हैं। जिले में 3.50 लाख से अधिक किसान 10% के प्लॉट की मांग से प्रभावित हैं इसके बावजूद सरकार किसानों के दमन और उत्पीड़न पर लगी हुई है। आज किसान हजारों की संख्या में फिर से जीरो प्वाइंट पर इकट्ठा होंगे। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे।

उधर, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर कहा गया है कि छह दिसंबर को भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। विभिन्न संगठन बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धरने प्रदर्शन कर सकते हैं।

अराजक तत्व माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास कर सकते हैं। यह तिथि काफी संवेदनशील है। दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों के महापड़ाव को लेकर सतर्क है पुलिस किसान एक बार फिर दलित प्रेरणा स्थल पर महापड़ाव कर सकते हैं। पुलिस इसे रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। संविधान निर्माता के महापरिनिर्वाण दिवस को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है।

क्या डीप स्टेट भारत पर बुरी नज़र डाल रहा है? पिछले 3 वर्षों से संसद सत्र के आसपास विदेश की रिपोर्ट पर हंगामा क्या महज संजोग है?

डीप स्टेट पड़ोसी मुल्कों में सफ़ल मगर अमेरिका में नाकाम!क्या अब भारत पर बुरी नजर?
पड़ोसी मुल्कों अफ़गानिस्तान नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश का हाल हमने देखे क्या अब डीप स्टेट की बुरी नज़र सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर?- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर तेज़ी से बढ़ते भारत के कद प्रतिष्ठा रुतबे मान सम्मान से पूरी दुनियाँ हैरान है, क्योंकि भारत का रणनीतिक लक्ष्य विज़न 2047 के रोडमैप उम्मीद से कई गुना अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है, इसकी गूंज पूरे विश्व में होगी, साफ तौर पर अगर 4 सज्जन होंगे तो 24 दुश्मन भी पैदा होते हैं,जो भारत की दिशा को अपने अनुसार बढ़ाना या रोकना या अपना पावर सृजित करते हैं, इस क्रिया को डीप स्टेट की संज्ञा दी गई है, इसे ऐसे समूह के रूप में देखा जाता है जो गोपनीय तरीके से अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिना लोकतांत्रिक रूप से चुने ही देश पर राज करने की कोशिश करते हैं या अपने तरीके, मनमर्जी से सत्ता को चलना चाहते हैं। पिछले तीन संसादिय सत्रों से हम लगातार देख रहे हैं कि संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं विधेयक ध्वनि मत से पारित हो रहे हैं, जो पूरा विश्व देख रहा है, जिसका कनेक्शन डीप स्टेट से जोड़ा जा रहा है। दिनांक 5 दिसंबर 2024 को राज्यसभा की लाइव चल रही कार्यवाही में माननीय सभापति महोदय ने पहली बार डीप स्टेट शब्द का उल्लेख किया है ।सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता राज्यसभा सदस्य ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे जिसकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश का हाल हमने देखे क्या अब डीप स्टेट की सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर बुरी नजर की संभावना है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे भारत का तेजी से विकास हैट्रिक स्थाई सरकार से नकारात्मक सोच वाले समूह जिसमें भारत विरोधी अमेरिकी उद्योगपति भी शामिल है, 3 वर्षों से संसद सत्र अवधि केआसपास विदेश की रिपोर्ट पर हंगामा क्या सिर्फ सयोंग है?

साथियों बात अगर हम भारत में डीप स्टेट की संभावना की करें तो, दुनियाँ के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा भारत डीप स्टेट के निशाने पर है, भारत में अपने एजेंटों की मदद से डीप स्टेट देश विरोधी हरकतों कोसमय-समय पर हवा देता रहता है ।डीप स्टेट भारत में हजारों एनजीओ को भी घूमा-फिराकर वित्त पोषित करता है ताकि राजनितिक गतिरोध और प्रशासनिक अस्थिरता का माहौल बनाए रखा जा सके हालांकि, भारत में डीप स्टेट की सक्रियता और असर को लेकर कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक गतिरोधों केदौरान अक्सर यह बहस का हिस्सा बनता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों को पश्चिमी ताकतों और डीप स्टेट की भारत को अस्थिर करने की साजिशों के बारे में आगाह किया जा चुका है। भारत इन ताकतों की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा है, क्योंकि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से दुनिया के कई देश और कारोबारी परेशान हैं। साल 2019 में भारत का शेयर बाजार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 77 प्रतिशत था जो 2023-24 में बढ़कर 124 प्रतिशत हो गया है, इसके अलावा वैश्विक बाजार में डॉलर के इस्तेमाल को कम करने के बीच भारतीय रुपये का प्रचलन बढ़ रहा है। इसके अलावा, भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रैटिजिक अटॉनमी) की मजबूत परंपरा को फिर से तरजीह दी जा रही है. इसलिए, भारतीय कारोबारी उद्योगपति के साथ ही सेबी जैसी बाजार नियामक संस्था पर हमला कर एलआईसी, एसबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे बैंकों जैसे प्रमुख सरकारी संस्थानों में दहशत फैला दी गई थी, उन ताकतों का मानना था कि भारतीय बाजार में उथल-पुथल का सीधा असर लाखों मध्यवर्गीय

लोगों और निवेशकों पर पड़ेगा और अफातफरी मच सकती है, हालांकि, ऐसा नहीं हो सका और भारतीय बाजार ने इस रोलर कोस्टर को आसानी से पार कर लिया था।

साथियों बात अगर हम लगातार पिछले तीन वर्षों से बाधित होने के दिनांक 5 दिसंबर 2024 को उच्च सदन के सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों द्वारा सवाल उठाने की करें तो, भाजपा सांसद ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से ये क्या संयोग है?, जब भारत की संसद का सत्र चलता है, तभी ये रिपोर्ट्स आती हैं ।पूर्व में भारत के किसानों को लेकर रिपोर्ट सामने आई, तब भी संसद सत्र चल रहा था और इसी तरह पेगासस और हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी लगभग उसी समय सामने आईं, जब भारत की संसद का सत्र या तो चल रहा था या शुरू होने वाला था। अब बजट सत्र शुरू होने से पहले भारत के उद्योगों के बारे में अमेरिकी अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है। क्या ये महज संयोग है या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा है। विगत लोकसभा चुनाव में रूस की सरकार ने भी साफ कहा था कि भारत के चुनाव में हस्तक्षेप की कोशिश हो रही है। ये पहली बार हुआ, जब किसी सरकार ने देश के चुनाव में हस्तक्षेप की बात कही। हिंडनबर्ग की भ्रामक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने ने कहा कि 22 जुलाई से 09 अगस्त के बीच संसद का मानसून सत्र हुआ और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। वहीं 25 नवंबर से वर्तमान सत्र शुरू हुआ और 20 नवंबर को एक अमेरिकी कोर्ट में अटार्नी की रिपोर्ट जारी हुई। क्या यह एक महज संयोग है?भाजपा सदस्य ने कहा कि 20 जुलाई, 2023 को संसद सत्र की शुरुआत होने वाली थी और 19 जुलाई को मणिपुर का वीडियो सामने आया था। क्या यह सब महज एक संयोग था? ।उन्होंने एक के बाद कई रिपोर्टों का जिक्र करते हुए इसे भारत को अस्थिर करने की साजिश बताया। उच्च सदन में उनके भाषण के दौरान विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इस बात पर एतराज जताया किशून्यकाल में 3 मिनट से अधिक नहीं बोलने का प्रावधान होने के बावजूद वह अपनी बात रखे जा रहे हैं,इसपर राज्यसभा के सभापति ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और इस पर हर किसी के विचार आने चाहिए, उन्होंने कहा, पूरे सदन को एकजुट रहना चाहिए अगर ऐसा कोई ट्रेंड है, ऐसी कोई पहल है,जो खतरनाक है, जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है ।इसके साथ ही उन्होंने सदस्य को अपनी बात पूरी करने की इजाजत दी ।सभापति की अनुमति के बाद विपक्षी सदस्यों के तेज होते हंगामे के बीच सदस्य ने आगे कहा, विशेष कर पिछले तीन सालों में जब से विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, विदेश की ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं, जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक, नैतिक और सामाजिक पक्ष पर हमला कर रही हैंउन्होंने ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंगप्रोजेक्ट की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसे विदेशी सरकारों की फंडिंग है और इसके केंद्र में भारत भी है,इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट से विवादित अमेरिकी कारोबारी जार्ज सोरोस का भी संबंध भी बहुत गहरा है।

साथियों बात अगर हम डीप स्टेट को गहराई से समझने की करें तो,डीप स्टेट क्या है? कहां से आया, क्या है मतलब और मकसद? कैंब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक डीप स्टेट ऐसे समूह को कहा जाता है जो गोपनीय तरीके से अपने विशेष हितों को पूरा करने और उसकी रक्षा के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के बगैर देश पर राज करने के लिए काम करते हैं। डीप स्टेट शब्द को तुर्की डेरिन डिलेट (गहरा/ गहन राज्य) का एक अनुवाद माना जाता है, राजनीतिक तौर पर समझें तो डीप स्टेट एक प्रकार की समानांतर सरकार है,इसको किसी देश में संभावित रूप से गुप्त और अनधिकृत ताकतों के नेटवर्क से बनी सत्ता के तौर पर देखा जाता है ।डीप स्टेट किसी भी राज्य के राजनीतिक नेतृत्व से अलग स्वतंत्र रूप से अपने निजी एजेंडे और लक्ष्यों की खोज में काम करती है। पब्लिक स्फीयर में यह शब्द काफी ज्यादा नकारात्मक अर्थ रखता है और अक्सर इसका मकसद साजिश के सिद्धांतों से जुड़ा होता है ।अमेरिका में दोबारा लौट रहे ट्रंप युग के बीच डीप स्टेट शब्द काफी चर्चा बटोर रहा है, डीप स्टेट की थ्योरी में भरोसा रखने वालों के मुताबिक, ये चुने हुए प्रतिनिधियों के समानांतर चलने वाला एक सिस्टम है। इसमें मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के लोग भी शामिल होते हैं और सरकार से अलग अपनी नीतियां लागू करते या उसे प्रभावित करते हैं ।स्पुतनिक इंडिया ने वैश्विक उद्योग सूत्रों के हवाले से बताया है कि डीप स्टेट का मकसद भारतीय संस्थानों और कारोबारियों में जनता का विश्वास कमजोर करना है। बांग्लादेश समेत दक्षिण एशिया के कई देशों के अलावा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान साफ तौर पर यूएस डीप स्टेट की भूमिका देखी गई थी। अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार के दौरान जानलेवा हमले के बाद सार्वजनिक तौर पर इसको लेकर गंभीर चिंता जताई थी।

अतः अगर हम उपरोक्त पुरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि क्या डीप स्टेट भारत पर बुरी नज़र डाल रहा है? पिछले 3 वर्षों से संसद सत्र के आसपास विदेश की रिपोर्ट पर हंगामा क्या महज संजोग है? डीप स्टेट पड़ोसी मुल्कों में सफ़ल मगर अमेरिका में नाकाम !क्या अब भारत पर बुरी नजरपड़ोसी मुल्कों अफ़गानिस्तान नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश का हाल हमने देखे,क्या अब डीप स्टेट की बुरी नज़र सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर?

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV Drive the Future

बजाज ऑटो इस महीने अगली पीढ़ी का चेतक ई-स्कूटर लॉन्च करेगा

परिवहन विशेष न्यूज

जनवरी 2020 में पहली बार लॉन्च किए गए बजाज चेतक के लिए सबसे बड़ा अपडेट यह होगा कि अगली पीढ़ी के मॉडल में नया चेसिस और अधिक स्टोरेज स्पेस होगा।

बजाज ऑटो, जो अपने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की मजबूत मांग देख रहा है और जिसने जनवरी-नवंबर 2024 में 1,74,909 इकाइयों की खुदरा बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल की तुलना में 184% अधिक है, चेतक के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट लॉन्च करने वाला है।

इस अपडेट के पीछे की चेतक की व्यावहारिकता को बेहतर बनाना है। एथर रिज्टा, ओला एस1 और टीवीएस आईक्यूब जैसे प्रतिद्वंद्वी सभी बहुत ज़्यादा जगह देते हैं और बजाज ऑटो उनसे मेल खाने पर काम कर रहा है। ऐसा करने के लिए, कंपनी ने एक नया चेसिस डिज़ाइन किया है जो बैटरी पैक को फ़्लोरबोर्ड के नीचे ले जाता है, जिससे ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा।

नए बैटरी पैक डिज़ाइन की ओर बढ़ने से क्षमता भी बढ़ सकती है और इस तरह, लंबी दूरी तय करने में मदद मिल सकती है। हालाँकि, वर्तमान में कंपनी द्वारा बजाज चेतक मॉडल के आधार पर 123 से 137 किमी की रेंज का दावा किया गया।

स्कूटर के अन्य पहलू, जिसमें डिज़ाइन भी शामिल है, के अपरिवर्तित रहने की संभावना है। बजाज ऑटो ने पाया है कि चेतक के डिज़ाइन को सभी आयु वर्ग के ग्राहकों से व्यापक स्वीकृति मिली है और वह इस फ़ॉर्मूले से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। इसमें नई रंग योजनाएँ होने की संभावना है लेकिन दृश्य परिवर्तन की सीमा यही होने की संभावना है।

नई पीढ़ी के बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिसंबर के मध्य में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसकी कीमत मौजूदा मॉडल के करीब ही रहने की संभावना है।

जम्मू विश्वविद्यालय ने कैंपस में चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध

परिवहन विशेष न्यूज

पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जम्मू विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में गुरुवार, 05 दिसम्बर से चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया हैं।

विश्वविद्यालय की हरित पहल का हिस्सा का कदम बताते हुए चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर प्रकाश अंताहल ने कहा कि यूनिवर्सिटी में ग्रीन कैंपस पहल को लागू करने की योजना काफी समय से थी, लेकिन पार्किंग की जगह न होने के कारण इसमें देरी हुई।

उन्होंने कहा, ₹अब जब पार्किंग सुविधा तैयार हो गई है, तो विश्वविद्यालय ने हरित परिसर की दिशा में यह निर्णायक कदम उठाया है।"

चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध, कार्बन उत्सर्जन को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने तथा पैदल यात्रियों के अनुकूल परिसर को बढ़ावा देने के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रोफेसर अंताहल ने कहा, ₹इस उपाय का उद्देश्य स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।₹ उन्होंने आगे कहा, ₹विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, हमें विश्वास है कि यह कदम शैक्षणिक संस्थानों में स्थिरता के लिए एक मानक स्थापित करेगा।"

विश्वविद्यालय ने इस नई प्रणाली को सुचारू रूप से अपनाने के लिए प्रावधान किए हैं। परिसर में दोपहिया वाहनों की अनुमति जारी रहेगी, विभागीय क्षेत्रों में समर्पित पार्किंग स्थल आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त परिसर समुदाय के लिए सुविधा और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ई-वाहन और साइकिल जैसे वैकल्पिक परिवहन मोड निर्दिष्ट स्थानों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

नेतृत्व के प्रदर्शन के रूप में कुलपति प्रो. उमेश राय भी परिसर के भीतर वाहन का उपयोग करने से परहेज करेंगे, जिससे इस परिवर्तनकारी बदलाव के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता पर बल मिलेगा।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर मीना शर्मा ने कहा, ₹जम्मू विश्वविद्यालय के कैम्पस में चार पहिया वाहनों को प्रतिबंधित करने का निर्णय पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल वायु गुणवत्ता को बढ़ाने और सभी हितधारकों के लिए एक स्वस्थ, पैदल यात्री-अनुकूल स्थान को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। वैकल्पिक परिवहन विकल्पों के साथ, यह परिवर्तन सुविधा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी दोनों सुनिश्चित करता है। मैं सभी से इस बदलाव को अपनाने और हमारे परिसर को स्थिरता और हरित प्रथाओं का एक मॉडल बनाने में सामूहिक रूप से योगदान देने का आग्रह करती हूं।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नागरिक समाज और जनता को इस परिवर्तनकारी निर्णय के बारे में जानकारी देने का अवसर भी प्रदान किया। विश्वविद्यालय छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और व्यापक समुदाय सहित सभी हितधारकों से अपील करता है कि वे इस पहल को सफल बनाने में अपना सहयोग दें।

जम्मू विश्वविद्यालय ने 1095 किलोवाट ग्रिड-आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर स्ट्रीट लाइट, एलईडी लाइटिंग, छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली, वर्मीकंपोस्टिंग, बायोगैस संयंत्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जैसी कई अन्य ग्रीन कैंपस पहलों के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को लगातार बढ़ावा दिया है। कैंपस पहले से ही साइकिल और ई-वाहनों जैसे प्रदूषण मुक्त विकल्पों को बढ़ावा देता है, जिससे शिक्षा मंत्रालय से जिला ग्रीन चैंपियन पुरस्कार और आईएसओ 14001-2015 प्रमाणन जैसे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

खरीदने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, पहले जान लीजिए कितने में आएगी ई-स्कूटरों की नई बैटरी?

परिवहन विशेष न्यूज

हाल के समय में लोग पेट्रोल की जगह पर इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इन्हें एक बार चार्ज करने पर 100 से 150 किमी तक का रेंज मिलता है। यह काफी किफायती होती है लेकिन इनमें सबसे बड़ा खर्च बैटरी का होता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी बदलवाने में कितना खर्च करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग बढ़ी है। दरअसल, यह पेट्रोल से चलने वाले स्कूटरों से काफी किफायती होने के साथ ही पेट्रोल भरवाने का झंझट नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग खर्च में भारी बचत करते हैं। इन्हें बस चार्जिंग की जरूरत होती है जो बहुत सस्ती होती है। हालांकि, इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर सबसे बड़ा खर्च बैटरी का होता है। अगर स्कूटर की बैटरी खराब हो जाए तो उसे बदलवाना काफी महंगा साबित होता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की नई बैटरी कितने में आपको पड़ेगी।

EVIndia ने शेयर की बैटरियों की कीमत

हाल ही में EVIndia ने मार्केट में मिलने वाले कुछ पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बैटरी की कीमत की जानकारी शेयर की है। इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों में Ather Rizta, Ather 450X, TVS iQube, Vida V1 और Bajaj Chetak स्कूटर की बैटरी की कीमतों के बारे में बताया है। आइए जानते हैं कि इनकी बैटरी कितने में आती है।

Ather 450X और Rizta की बैटरी कीमत

Ather 450X के 2.9 kWh बैटरी पैक मॉडल की नई बैटरी की कीमत 65,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये के बीच है। वहीं, Ather 450X के 3.7 kWh बैटरी पैक मॉडल की बैटरी की कीमत 80,000 रुपये के आसपास है।

एथर के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर रिज्टा की बात करें तो इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट की कीमत 65,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक है।

Vida की बैटरी कीमत

हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida दो वेरिएंट के साथ आती है, जो V1 Pro और V1 Plus है। Vida V1 Pro की बैटरी रिप्लेस करने की कीमत करीब 85,000 रुपये और V1 Plus की बैटरी की कीमत 75,000 रुपये तक है।

TVS iQube की बैटरी कीमत

TVS की iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर कई वेरिएंट के साथ आती है। टीवीएस आईक्यूब के स्टैंडर्ड मॉडल की बैटरी कीमत की बात करें तो यह 60,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये के बीच आती है। वहीं, TVS iQube ST की नई बैटरी की कीमत करीब 90,000 रुपये तक है।

Bajaj Chetak की बैटरी कीमत

बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर Chetak दो बैटरी पैक वेरिएंट के साथ आता है, जो 2.8kWh (Chetak 2901) और 3.2kWh (Chetak 3201) है। अगर आपको इन स्कूटरों में बैटरी रिप्लेसमेंट की जरूर पड़ जाए तो आपको 60,000 रुपये से 80,000 रुपये तक का खर्च करना पड़ सकता है।

सन मोबिलिटी की मॉड्यूलर बैटरी-स्वैपिंग तकनीक का लक्ष्य भारी वाहन बेड़े का विद्युतीकरण करना

परिवहन विशेष न्यूज

वीरा वाहना के साथ साझेदारी में सन मोबिलिटी ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत की पहली मॉड्यूलर बैटरी-स्वैपिंग तकनीक का प्रदर्शन किया। पूरी तरह से एकीकृत मोबिलिटी समाधान को बस और ट्रक बेड़े को विद्युतीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो वाणिज्यिक बेड़े, विशेष रूप से भारी वाहनों को विद्युतीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो उत्सर्जन में कटौती, वायु गुणवत्ता में सुधार और समग्र परिवहन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी समाधान ने बसों के लिए 10,000 से अधिक पूछताछ को आकर्षित किया और तमिलनाडु में बस ऑपरेटरों पर ध्यान केंद्रित किया।

सन मोबिलिटी ने क्षेत्र के कई प्रमुख बस ऑपरेटरों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारी-भरकम वाहनों के विद्युतीकरण में बैटरी-स्वैपिंग तकनीक की क्षमता पर जोर दिया गया। मॉड्यूलर स्वैपिंग तकनीक एक व्यावहारिक, लागत-प्रभावी समाधान प्रदान करती है जो ऑपरेटरों के लिए दक्षता को बढ़ाती है और परिचालन लागत को कम करती है। बैटरी स्वैपिंग से बसों की शुरुआती लागत में 40 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे यह पारंपरिक ICE बसों की शुरुआती लागत के बराबर हो जाएगी। इसके साथ ही वित्तपोषण तक आसान पहुंच से बेड़े के मालिकों द्वारा ईवी को अपनाने में प्रवेश की बाधा दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह बेड़े के ऑपरेटरों की परिचालन लागत को 20 प्रतिशत तक कम करता है, जिससे तीन मिनट से कम समय में होने वाली त्वरित स्वैपिंग प्रक्रिया के कारण बसों का अपटाइम और अधिक उपयोग बढ़ जाता है।

इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए बैटरी स्वैपिंग आवश्यक है और इससे ईवी को अपनाने को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। दो, तीन और छोटे चार पहिया वाहनों की श्रेणी में, सन मोबिलिटी ने 2017 में अपनी स्थापना के बाद से 26,000 से अधिक वाहनों को शामिल किया है। फर्म के पास देश भर में 650 से अधिक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हैं और यह प्रतिदिन लगभग 1.6 मिलियन किलोमीटर और 60,000 बैटरी स्वैप करता है, जो पिछले साल के उपयोग की तुलना में 84 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि है।

ओमान और बेल्जियम ने वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को आकार देने के लिए रणनीतिक हरित हाइड्रोजन समझौते की घोषणा

परिवहन विशेष न्यूज

ओमान और बेल्जियम ने ग्रीन हाइड्रोजन में अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक की बेल्जियम की राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य हाइड्रोजन उद्योग में सहयोग बढ़ाना है। हाइड्रोजन ओमान (हाइड्रोम) और बेल्जियम हाइड्रोजन काउंसिल के बीच यह समझौता हाइड्रोजन उत्पादन, बुनियादी ढांचे, परिवहन और उपयोग पर केंद्रित होगा।

यह समझौता ज्ञापन वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ओमान अपने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, जबकि बेल्जियम यूरोप के लिए एक प्रमुख हाइड्रोजन औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित है। साथ मिलकर, उनका लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना और एक निर्बाध वैश्विक हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला बनाना है।

यह समझौता ओमान और बेल्जियम के बीच दशकों पुराने मज़बूत संबंधों पर आधारित है, जिसमें हरित ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले मील के पत्थर भी शामिल हैं। समझौता ज्ञापन के तहत पहले चरण में ज्ञान साझा करना, प्रौद्योगिकी विकास और हाइड्रोजन उत्पादन और शिपिंग बुनियादी ढांचे की योजना बनाना शामिल होगा।

महामहिम के नेतृत्व द्वारा समर्थित, हरित हाइड्रोजन पर ओमान का निरंतर ध्यान देश को हाइड्रोजन नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। बेल्जियम के साथ साझेदारी का उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देना और हाइड्रोजन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के अवसरों का विस्तार करना है।

ठंड में कार की बैटरी न हो जाए खराब, परफॉर्मेंस बरकरार रखने के लिए फॉलों करें 5 टिप्स

परिवहन विशेष न्यूज

सर्दियों में कार की बैटरी काफी जल्दी ही खराब होने के साथ ही कैपेसिटी भी कम हो जाती है। कार की बैटरी खराब होने की वजह से उसे स्टार्ट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि ठंड के मौसम में कार की बैटरी को किस तरह से सेफ रख सकते हैं।

नई दिल्ली। ठंड के मौसम में अक्सर देखने के लिए मिलता है कि कार की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है या फिर वह खराब हो जाती है। जैसे-जैसे तापमान गिरता है, बैटरी की कैपेसिटी कम होने लगती है। जिसकी वजह से कार को स्टार्ट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। इस समस्या से बचने के लिए हम आपको यहां पर कुछ आसान तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप ठंड में अपनी कार की बैटरी को ठीक रख सकते हैं।

1. नियमित रखरखाव करें

सर्दी में बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए रखने के लिए उसकी सही से देखभाल करना जरूरी है। सबसे पहले बैटरी के टर्मिनल्स को चेक करें और यह देखें कि वहां पर जंग तो नहीं लगा हुआ है। अगर जंग लगी हो तो उसे बेकिंग सोडा और पानी से साफ करें। इससे कार की बैटरी की पावर बढ़ने के साथ ही उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगी।

2. बैटरी वार्मर कार में रखें

ठंड के मौसम में अपनी कार में बैटरी वार्मर जरूर रखें। इसका रखने का आपको यह फायदा होगा कि इससे आप बैटरी के ठंडे होने पर आसानी से गर्म कर सकते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बनी रहती है और बैटरी जल्दी खराब भी नहीं होती है।

3. कम दूरी का सफर न करें

अगर आप कार से कम दूरी का सफर करते हैं तो उसकी वजह के गाड़ी को बार-बार स्टार्ट करना पड़ता है। इससे बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। इस वजह से छोटे सफर में बैटरी को पूरा चार्ज होने का समय नहीं मिलता है। जिसकी वजह से कोशिश करें कि जब आपको लंबा सफर करना हो तो कार का इस्तेमाल करें।

4. गैरजरूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद रखें

कार में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिए होते हैं, जैसे- लाइट्स, हीटर और इंफोटेनमेंट सिस्टम। जब यह सब ऑन रहते हैं तो बिना जरूरत के बैटरी की पावर को कंज्यूम करते रहते हैं। जिसकी वजह से जब आप कार बंद करें तो इन सभी चीजों को बंद कर लें, ताकि बैटरी पर दबाव न पड़ें और उसकी लाइफ भी बढ़ें।

5. सिंथेटिक ऑयल यूज करें

ठंड के मौसम में कार के इंजन के लिए सिंथेटिक ऑयल को बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह आसानी से बहता है। इस वजह से यह इंजन को ठंड में जल्दी स्टार्ट करने में भी मदद करता है। इससे बैटरी पर भी दबाव कम पड़ता है। इसकी वजह से बैटरी की उम्र भी बढ़ती है।

मानव जीवन में संगीत का महत्व

विजय गर्ग

संगीत कला का एक रूप है. जब विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को एक साथ रखकर या मिश्रित करके एक नई ध्वनि बनाई जाती है जो मनुष्य को अच्छी लगती है तो उसे संगीत कहा जाता है। संगीत ग्रीक शब्द मूसिके से लिया गया है, जिसका अर्थ है संगीत की कला। म्यूज़ में प्राचीन ग्रीस में संगीत, कविता, कला और नृत्य की देवी शामिल थीं। संगीत में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो लोग गाते हैं, और दूसरा संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि। संगीत बनाने वाले व्यक्ति को संगीतकार कहा जाता है। प्रत्येक ध्वनि को संगीत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ध्वनि शोर या संगीत हो सकती है। संगीत वह ध्वनि है जो मनुष्य के कान को तो अच्छी लगती है परंतु शोर नहीं। यह भी संभव है कि जो ध्वनि एक व्यक्ति के लिए संगीत हो, वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए शोर हो। उदाहरण के लिए, तेज़ रॉक संगीत या हिप-हॉप किशोरों या युवा पीढ़ी के लिए संगीत है लेकिन यह बुजुर्गों के लिए शोर है। संगीत की उत्पत्ति ऐसे कई सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि संगीत की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संगीत उस समय से भी पहले अस्तित्व में था जब मनुष्य अस्तित्व में आया। उन्होंने संगीत को छह युगों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक युग को संगीत शैली में परिवर्तन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन परिवर्तनों ने उस संगीत को आकार दिया है जिसे हम अब सुनते हैं। पहला युग मध्ययुगीन या मध्य युग था। यह युग पॉलीफोनी और संगीत संकेतन की शुरुआत का प्रतीक है। मोनोफोनिक संगीत और पॉलीफोनिक संगीत दो मुख्य प्रकार के संगीत थे जो उस युग में लोकप्रिय थे। इस युग में, नए उभरे ईसाई चर्चों ने विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिन्होंने संगीत की नियति तय की। यही वह समय था जब ग्रेगोरियन मंत्र नामक संगीत को एकत्रित और संहिताबद्ध किया गया था। उनके युग में ऑर्गेनम नामक एक नये प्रकार के संगीत का भी सृजन हुआ। संगीत का महान नाम गुइलाउम डी मचौत इसी युग में प्रकट हुआ। इस युग के बाद पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण शब्द का शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म है। यह युग सीए 1420 से 1600 तक था। इस समय पवित्र संगीत चर्च की दीवारें तोड़कर स्कूलों में फैलने लगा। स्कूलों में संगीत रचा जाने लगा। इस युग में नृत्य संगीत एवं वाद्य संगीत बहुतायत में किया जाने लगा। पुनर्जागरण काल के अंत में अंग्रेजी मेड्रिगल भी फलने-फूलने लगा। इस प्रकार का संगीत विलियम बर्ड, जॉन डाउलैंड, थॉमस मॉर्ले और कई अन्य लोगों द्वारा रचा गया था। इसके बाद, बारोक युग आया जो सीए 1600 में शुरू हुआ और 1750 में समाप्त हुआ। बारोक शब्द एक इतालवी शब्द बारोको से लिया गया है जिसका अर्थ विचित्र, अजीब या अजीब है। इस युग की विशेषता संगीत पर किये गये विभिन्न प्रयोग हैं। इस उम्र में वाद्य संगीत और ओपेरा का विकास शुरू हुआ। जोहान सेबेस्टियन बाख इस काल के महान संगीतकार थे। इसके बाद शास्त्रीय युग आया जो मोटे तौर पर 1750 में शुरू हुआ और 1820 में समाप्त हुआ। संगीत की शैली बारोक युग के भारी सजावटी संगीत से सरल धुनों में बदल गई। पियानो संगीतकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक वाद्ययंत्र था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना यूरोप का संगीत केंद्र बन गई। पूरे यूरोप से संगीतकार संगीत सीखने के लिए वियना आते थे। इस युग में जो संगीत रचा गया, उसे अब संगीत की विनीज़ शैली कहा जाता है। अब रोमांटिक युग आया जो 1820 में शुरू हुआ और 1900 में समाप्त हुआ। इस युग में संगीतकारों ने अपने संगीत में बहुत गहरी भावनाएँ जोड़ीं। कलाकारों ने संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध की विशेषता स्वर्गीय रोमांटिक संगीतकारों की थी। जैसे-जैसे सदी बदली, वैसे-वैसे संगीत भी बदला। अब आयाबीसवीं सदी का संगीत. इस चरण की विशेषता कई नवाचार हैं जो संगीत में किए गए थे। नए प्रकार के संगीत का निर्माण हुआ। ऐसी प्रौद्योगिकियाँ विकसित की गईं जिससे संगीत की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। संगीत का महत्व संगीत हमारे जीवन में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। यह उससे कुछ अधिक है. संगीत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। संगीत हमें रचनात्मक बनाता है: संगीत रचनात्मकता की कुंजी है। संगीत हमारे दिमाग को बेहतर बनाता है। यह इसे और अधिक रचनात्मक और नवीन बनाता है। संगीत हमारे दिमाग को कला से भर देता है और हर महान आविष्कार के लिए कला, रचनात्मकता और कल्पना की आवश्यकता होती है। कभी-कभी ये क्षमताएँ संगीत द्वारा प्रदान की जाती हैं। संगीत हमारी समझने की क्षमता को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हमें उसके बोल समझ में आते हैं। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि गायक अपने गीत के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। जब कोई व्यक्ति वाद्य संगीत सुनता है तो वह शब्दों का उपयोग किए बिना यह समझने के लिए अपने दाहिने मस्तिष्क का उपयोग कर रहा है कि संगीतकार अपने संगीत के साथ क्या कहना चाह रहा है। दूसरी ओर, जब हम कोई वाद्ययंत्र बजा रहे होते हैं, तो हम वह स्वर बजाते हैं जो हमारे विचारों और हमारी भावनाओं को दर्शाता है। इस प्रक्रिया में, हम बोलने की क्षमता का उपयोग किए बिना, केवल संगीत के साथ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। जब हम संगीत में अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, तब हम संगीत के बारे में सोचते हैं, जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे दिमाग को और अधिक रचनात्मक बनाता है। और एक रचनात्मक दिमाग कई नई और उपयोगी खोजें कर सकता है। संगीत सीखने को अधिक मनोरंजक बनाता है: याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए संगीत एक बहुत ही प्रभावी उपकरण है। हम सभी ने देखा है कि हम अपने पाठ्यक्रम को सीखने की तुलना में एक गाना बहुत आसानी से और तेजी से सीख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मन संगीत का आनंद लेता है। हमारा मन जिस चीज का आनंद लेता है, उसे वह अपने पास रख लेता है। यह इस तथ्य से संबंधित हो सकता है कि जब भी हम अपने जीवन का आनंद लेते हैं तो वे क्षण हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाते हैं। इसलिए, जब हमें कुछ सीखना है तो हमें आनंद लेना होगा। इसके लिए संगीत एक अच्छा विकल्प है. जब भी छात्र अपनी स्कूली शिक्षा या प्री-स्कूलिंग शुरू करते हैं, तो शिक्षक उन्हें सबसे पहले कविताएँ सिखाते हैं। वे छोटे बच्चों को कविताएँ सुनाते हैं। छात्रों को यह बहुत रोचक लगता है और वे इसे अपने दिमाग में रखते हैं। कविताओं में संगीत उन्हें और अधिक मनोरंजक बनाता है। शायद यही कारण है कि हम सभी को बचपन में सिखाई गई कविताएं अब तक याद हैं और भविष्य में भी वे हमारे दिमाग में रहेंगी। छात्रों को गुणन सारणी सिखाने के लिए संगीत का उपयोग किया गया है। जब छात्र गुणन सारणी को गीत के रूप में गाते हैं, तो वे इसका आनंद लेते हैं और इसे अपने दिमाग में बनाए रखते हैं। संगीत हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है: हममें से अधिकांश, जब हम अपने पसंदीदा संगीत को सुनकर दुखी होते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संगीत हमारे लिए तनाव दूर करने का काम करता है। जब हम संगीत सुनते हैं तो हम आराम और शांति महसूस करते हैं। लेकिन हर तरह का संगीत हमें खुश नहीं कर सकता. यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का संगीत सुन रहे हैं। संगीत कुछ ही सेकंड में हमारा मूड बदल सकता है। जब हम कुछ डांस बीट्स

सुन रहे होते हैं, तो हम उसका आनंद ले रहे होते हैं और कभी-कभी उस पर डांस भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई आकर अचानक म्यूजिक रैक बदल दे और कोई उदास इमोशनल गाना डाल दे तो हमारा मूड अचानक बदल जाता है। गानों में छुपी भावनाओं को हम तुरंत महसूस करने लगते हैं। संगीत मूड स्विंग का कारण बनता है। यही कारण है कि जब हम उदास महसूस करते हैं तो हमें ऐसे गाने सुनने चाहिए जो हमें खुश कर दें। जब हम दुखी हों तो हमें वह संगीत सुनना चाहिए जो ऊर्जा से भरपूर हो, न कि वह जो बहुत दुखद या भावनात्मक हो। जब कोई बुरी याद हमें परेशान कर रही हो तो कम से कम कुछ समय के लिए उस याद को भूलने के लिए संगीत एक बेहतरीन विकल्प है। अवसादग्रस्त लोगों के लिए भी संगीत एक बेहतरीन विकल्प है. संगीत उन्हें खुश, तनाव रहित, तनाव मुक्त, शांत महसूस कराएगा और उन्हें आनंद देगा। इसलिए म्यूजिक किसी स्ट्रेस बस्टर से कम नहीं है। बच्चों के जीवन में संगीत का महत्व ऐसा नहीं है कि केवल वयस्क ही संगीत से लाभान्वित होते हैं बल्कि छोटे बच्चे भी संगीत से लाभान्वित होते हैं। संगीत बच्चों के भाषाई कौशल को विकसित करता है: गाने और कविताएँ बच्चों में प्रारंभिक अवस्था में ही भाषा कौशल विकसित करते हैं। बच्चे बोलना, पढ़ना या लिखना शुरू करने से पहले ही आवाज, स्वर और शब्दों को पहचानना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे गाने या कविता के रूप में संगीत सुनते हैं तो उनमें इस्तेमाल किए गए शब्दों का उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे समझने लगते हैं कि संगीत के रूप में उन तक क्या पहुंचाया जा रहा है। वे कल्पना करने लगते हैं कि क्या गाया जा रहा है। वे उनमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। संगीत उनके लिए एक भाषा बन जाता है। वे संगीत में प्रयुक्त भाषा पर पकड़ बना लेते हैं। संगीत बच्चों में सुनने का कौशल विकसित करता है: जब बच्चे संगीत सुन रहे होते हैं, तो इससे उनके सुनने के कौशल का विकास होता है। संगीत सुनकर, बच्चे विभिन्न स्वरों, आवाज़ों या धुनों के बीच अंतर कर सकते हैं। यह धीमी, कठोर या ऊंची आवाज की समझ और अर्थ विकसित करता है। वे एक व्यक्ति के विभिन्न मूड को जान लेते हैं जो संगीत और विभिन्न स्वरों का उपयोग करके व्यक्त किया जाता है। संगीत बच्चों में गति उत्पन्न करता है: गति और संगीत साझेदार हैं। जब बच्चे संगीत सुनते हैं, तो वे अपने शरीर को हिलाकर, अपना सिर हिलाकर या अपने पैरों को थपथपाकर या अपने हाथों से कुछ क्रियाएं करके इसका जवाब देते हैं। जब बच्चे संगीत सुनते समय हरकतें करते हैं तो इससे उनमें समन्वय कौशल विकसित होता है। संगीत चिकित्सा: संगीत के प्रयोग से किसी व्यक्ति को ठीक करने की सोच को संगीत चिकित्सा कहा जाता है। संगीत चिकित्सा कैंसर के रोगियों, एडीडी से पीड़ित बच्चों या मांसपेशियों में दर्द या अवसाद के रोगियों के लिए फायदेमंद है। कई अस्पतालों ने अपनी उपचार प्रक्रिया में संगीत चिकित्सा का उपयोग करना शुरू कर दिया है। शोध से पता चला है कि जब हम संगीत सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें संगीत की धुनों के साथ तालमेल बिठाती हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम तेज़ और ऊर्जावान संगीत सुनते हैं, तो यह हमारे मस्तिष्क में तीव्र एकाग्रता और सोच के स्तर में वृद्धि लाता है। दूसरी ओर, जब हम धीमा और शांत संगीत सुनते हैं, तो हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और हम मन की शांतिपूर्ण स्थिति प्राप्त करते हैं। हमारे मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन के साथ-साथ हमारे शरीर की कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन होता है। हम कह सकते हैं कि संगीत हमारे तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव डालता है जो हमारी सांस लेने की दर और दिल की धड़कन की दर को प्रभावित करता है। इस प्रकार संगीत डॉक्टर को रोगियों में दीर्घकालिक तनाव से निपटने और विश्राम को बढ़ावा देने में मदद करता है। निष्कर्ष मनोरंजन के अलावा संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे मस्तिष्क और उससे जुड़ी क्षमताओं का विकास करता है। यह बच्चों में कौशल विकसित करने और उन्हें पढ़ाने में भी फायदेमंद है। म्यूजिक थेरेपी खतरनाक और कुछ पुरानी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का संगीत सुन रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें असभ्य भाषा या अपमानजनक शब्द होते हैं जिन्हें बच्चों को नहीं सुनना चाहिए अन्यथा वे उन्हें अपने दिमाग में बनाए रखेंगे जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर, संगीत हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद है और इसे हर किसी के दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए।

समान शिक्षा समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है : विजय गर्ग

समान शिक्षा समाज और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भी मदद करती है। समान शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. सामाजिक समानता और न्याय:

समान शिक्षा से समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलते हैं, जिससे सामाजिक भेदभाव और असमानता कम होती है।

यह जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने में सहायक है।

2. गरीबी उन्मूलन:

शिक्षा से लोग आत्मनिर्भर बनते हैं और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं, जिससे गरीबी कम होती है।

एक समान शिक्षा प्रणाली गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करती है।

3. आर्थिक विकास:

अच्छी शिक्षा से कुशल मानव संसाधन तैयार होते हैं, जो देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करते हैं।

समान शिक्षा से देश की उत्पादकता बढ़ती है और राष्ट्रीय विकास को गति मिलती है।

4. लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन:

समान शिक्षा सभी नागरिकों को समान अवसर देकर लोकतंत्र को मजबूत करती है।

यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है।

5. लैंगिक समानता:

लड़कों और लड़कियों दोनों को समान शिक्षा देने से लैंगिक असमानता कम होती है।

यह महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है।

6. व्यक्तित्व विकास:

समान शिक्षा से बच्चों का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है।

यह उनकी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें निखारने का अवसर प्रदान करती है।

7. सामाजिक स्थिरता और शांति:

शिक्षा से लोग अधिक सहिष्णु, संवेदनशील और जागरूक बनते हैं, जिससे समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है।

यह अपराध दर को कम करने में भी मदद करती है।

8. वैज्ञानिक सोच और नवाचार:

समान शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है।

यह बच्चों को नई खोजों और नवाचारों के लिए प्रेरित करती है।

निष्कर्ष:

समान शिक्षा हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को पहचानने और एक बेहतर जीवन जीने का अवसर देती है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के हर स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है। समान शिक्षा का प्रसार एक ऐसा कदम है, जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी उज्ज्वल बना सकता है।

सकारात्मक शिक्षण स्थानों के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका

विजय गर्ग

एक सफल कक्षा केवल किताबों और संसाधनों के बारे में नहीं है; यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जहां छात्र सफल होने के लिए मूल्यवान, सुने जाने वाले और सशक्त महसूस करते हैं एक संपन्न शिक्षण कक्षा का आधार इस बात पर आधारित होता है कि छात्र अपनी कक्षा को किस तरह से समझते हैं। यह केवल उचित संसाधनों का उपयोग करने के बारे में नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह स्थापित करने के बारे में है जहां छात्र मान्यता प्राप्त, सुने जाने वाले और मूल्यवान महसूस करें। शिक्षक एक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और सुव्यवस्थित वातावरण का पोषण करके इसे संभव बनाने में प्रमुख उत्प्रेरक हैं जो छात्रों को उनकी क्षमता तक पहुंचने की अनुमति देता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने, सोच-समझकर जुड़ने और मील के पत्थर को मनाने के लिए रणनीतियों को लागू करके, शिक्षक एक शैक्षिक माहौल स्थापित कर सकते हैं जो प्रगति, आत्म-सम्मान और टीम वर्क का समर्थन करता है। शिक्षक एक सकारात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण स्थान बना सकते हैं: प्रत्याशा की भावना विकसित करें: शिक्षकों को अपने छात्रों को स्पष्ट निर्देश और प्रक्रियाएँ देनी चाहिए ताकि वे सहज महसूस करें। जब छात्रों को पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, तो पाठ के साथ उनकी बातचीत बढ़ जाती है और उनकी सीखने की क्षमताओं में उनका विश्वास बढ़ जाता है, जिससे उनका मूड शांत और केंद्रित हो जाता है। विद्यार्थियों की ज़रूरतों को संबोधित करें। कक्षा में कोई भी छात्र पूरी तरह से दूसरे के समान नहीं होता है। प्रशिक्षकों को शैक्षणिक और भावनात्मक जरूरतों की सराहना करनी चाहिए और सामग्री, ध्यान और प्रेरणा के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कक्षा में शिक्षार्थियों का स्वागत करें पहली छाप बहुत मायने रखती है। एक सरल मुस्कुराती हुई सुबह की शुभकामनाएं छात्रों को प्राप्त होती हैं और दिन का इंतजार करती हैं। एक स्वागत योग्य वातावरण कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी और भागीदारी का कारण बनता है। छात्रों के साथ बातचीत करें आदर्श रूप से, इससे शिक्षकों और छात्रों के बीच एक शक्तिशाली स्नेह तैयार करने में मदद मिलेगी। शिक्षकों को छात्रों के जीवन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए; उन्हें प्रश्न

पूछना चाहिए और उत्तरों पर ध्यान देना चाहिए। इससे विश्वास पैदा होता है, पढ़ने का कौशल विकसित होता है और छात्र अधिक बोलना चाहते हैं। टीम-निर्माण गतिविधियाँटीम-निर्माण गतिविधियाँ निर्देशों का अभ्यास करने और दूसरों के प्रति प्रशंसा दिखाने में मदद करती हैं। अनुभवशील बनें कभी-कभी, शिक्षकों की गलतियाँ, असफलताएँ और हानियाँ सीखने के माहौल को आरामदायक और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को जुड़ने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो दर्शाता है कि सीखना सामूहिक है और व्यक्तिगत नहीं। सफलता का जश्न मनाएं और छात्रों की सराहना करें: छात्रों की उपलब्धियों को पहचानने और उनका जश्न मनाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें फिर से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षकों को ऐसे व्यवहार को कक्षा में मौखिक प्रशंसा, पुरस्कार या अन्य प्रकार के पुरस्कारों से पुरस्कृत करना चाहिए। निर्णय से बचें: अनुकूल सीखने के माहौल में स्वीकार्यता और खुली मानसिकता स्पष्ट होती है। निर्णय को छात्रों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए ताकि छात्र स्वतंत्र रूप से अन्वेषण कर सकें और बिना हँसे गलतियाँ भी कर सकें। क्रोध को दबाएँ और रणनीतिक ढंग से कार्य करें: शिक्षकों से भावनात्मक विनियमन की अपेक्षा की जाती है। संघर्षों या समस्याओं के दौरान शांत रहना छात्रों की भावनाओं और समस्या-समाधान कौशल के लिए एक अच्छी मर्यादा के रूप में कार्य करता है, यह अभ्यास एक सीखने के माहौल की ओर ले जाता है जो शांत और लक्ष्य-उन्मुख होता है। उनके विचार सुनें छात्रों को अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देने से उन्हें अपने सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षकों को छात्रों को अपने मन की बात कहने में सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फीडबैक स्वीकार करें: शिक्षकों को किसी भी फीडबैक को प्रोत्साहित करना चाहिए और उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिएउनके छात्रों से. यदि छात्रों की प्रतिक्रिया के लिए उनकी सराहना की जाती है, तो माहौल संवादात्मक बन जाता है। कमरे को व्यवस्थित करना, छात्रों की देखभाल करना या उपलब्धि को पहचानना जैसी सरल गतिविधियां शिक्षकों को छात्रों के लिए एक सुरक्षित, मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य स्थान डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक स्वागत योग्य और पोषित कक्षा शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक उपलब्धि और भावनात्मक और सामाजिक विकास को सुविधाजनक बनाती है।

ज्ञानेंद्रियों की यात्रा

मनुष्यों को जन्म के साथ ही प्राकृतिक रूप वाणी मिलती है। मनुष्येतर अन्य जीवों को भी वाणी तो किसी न किसी रूप में मिलती ही है, पर मनुष्यों ने जिस रूप स्वरूप में वाणी द्वारा भाषाओं और संगीत को अपने जीवन को अभिव्यक्त करने वाले साधन के रूप में विस्तार दिया, यह बिंदु मानव सभ्यता के विकास और विस्तार का मूल है। मनुष्यों द्वारा अपने मुख से निकली ध्वनि के माध्यम से वाणी को विभिन्न भाषाओं में विकसित करना पृथ्वी के मनुष्यों का सबसे बड़ा सामूहिक कृतित्व, क्षमता या पराक्रम माना जा सकता है। वाणी, बुद्धि और विवेक के साथ ही सुनने की क्षमता अगर मनुष्य के पास न हो, तो मनुष्य बोल ही नहीं पाता। हालांकि यह क्षमता भी किसी में सामान्य, तो कहीं अलग-अलग तरीके से अमूमन सभी जीवों में होती है। वाणी होते हुए भी मनुष्य बोलना न चाहे या मौन रहना चाहे तो यह भी मनुष्य की अपनी प्राकृतिक शक्ति है ।

यही बात या ध्वनि सुनने को लेकर भी है । श्रवणेंद्रिय सुनने के लिए है, पर सुनना न सुनना यह मनुष्य की इच्छा पर है। कई बार हम कुछ सुन तो रहे होते हैं, मगर उसकी ग्राह्यता पर हमारा ध्यान नहीं होता, इसलिए वह न सुनने के बराबर हो जाता है। आंखें देखने के लिए हैं, जिसे हम दृष्टि की संज्ञा देते हैं, पर इस देखने की क्षमता से अलग मनुष्य के पास एक अंतर्दृष्टि भी होती है, जिसे मन की आंखों से देखा, सोचा या प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि के लिए न तो प्रकाश की जरूरत होती है, न आंखों की, केवल सोच-समझ और कल्पना शक्ति से निराकार रूप से सारा कुछ सोचा, समझा और मन ही मन प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। साकार चीजें देखने के लिए इंद्रियों की या ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता जरूरी है । पर निराकार कल्पना मन और बुद्धि का खेल है, प्रकृति प्रदत्त ज्ञानेंद्रियों और मनुष्य की सृजनात्मक और विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों की निरंतर जुगलबंदी ने आज की दुनिया को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जहां तक पहुंच कर हम समूची सभ्यता की सृजनात्मक शक्ति बढ़ा और नष्ट-भ्रष्ट भी कर सकते हैं। अब वापस फिर प्रागैतिहासिक सभ्यता में कोई एक व्यक्ति या समूचा मानव जगत भी नहीं पहुंच सकता । फिर भी आदिम से लेकर आज तक की कई सभ्यताएं एक साथ इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं अपने मूल अस्तित्व को बचाए रखने का अंतहीन संघर्ष करती दिखाई पड़ सकती है। मनुष्य कृत सभ्यताओं की समूची कहानी मनुष्य के सोच, विचार और कृतित्व का कमाल प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक और भविष्य में भी है, मनुष्य ने अपने जीवन में निरंतर बदलाव करते रहने की दिशा में बढ़ते रहकर सृजनात्मक प्रवृत्तियों को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाया है, जो आज के और भविष्य के मनुष्य के सामने एक तरह से नित नई चुनौतियों की तरह आ खड़ा हुआ है। पर मनुष्य को सृजनात्मक और विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों, दोनों को अपनाने में शायद एक अलग तरह का आनंद आता है। निरंतर चुनौतियां सामने न हों तो मानव सभ्यता को आगे बढ़ने का अवसर ही न मिले। यह सिद्धांत भी सामान्य रूप से माना जा सकता है।

मनुष्य की वाणी मूल रूप से ध्वनि के रूप में तो आमतौर पर एक समान ही प्रतीत होती है, पर किस समय किस रूप - स्वरूप और भाव के साथ वाणी का प्रयोग हुआ है, यह वाणी का प्रयोग करने वाले और

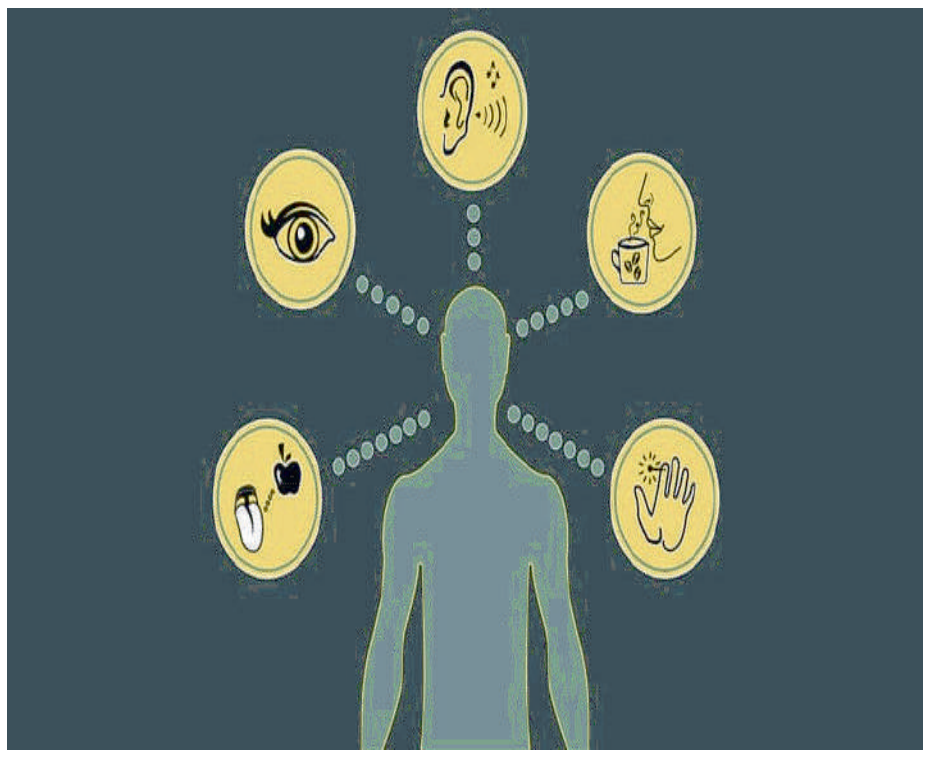

वाणी को सुनने वाले मनुष्य के मध्य वाणी के प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करता है । भाषा से अपरिचित अबोध बालक अपनी माता या अपने पिता या अन्य निकटवर्ती संबंधियों के भाव और आशय को समझने की प्राकृतिक क्षमता रखता है । यह समूचे मनुष्य जीवन या सभ्यता की अनोखी ज्ञान क्षमता है। तो क्या दृष्टि से मिलने वाले अबोध बालक के ज्ञान और समझ की क्षमताओं के विकास का मूल मनुष्य की देखने-सुनने और समझने की क्षमताओं या प्रत्यक्षीकरण से प्रारंभ होती है ? यह भी हमारे सोच-समझ का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है।

मानव सभ्यता में भाषाओं से ही समूची ज्ञान- यात्रा का उदय हुआ और साहित्य संस्कृति तथा सृजनात्मक सभ्यता के अंतहीन आयामों का रूप - स्वरूप मानव सभ्यता के स्थायी भाव बने । पर भाषा का ध्वनि स्वरूप और लिपि स्वरूप भी मानवीय सभ्यता का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। लिपि से जो ज्ञान- यात्रा प्रारंभ हुई, उसने समाज को दो रूप और स्वरूपों में विभाजित कर दिया । पढ़े-लिखे और बिना पढ़े-लिखे । बिना पढ़े-लिखे मनुष्य भाषा के ध्वनि-स्वरूप को तो अच्छे से समझते, जानते और बोलते हैं, पर लिपि स्वरूप को नहीं जानते या पढ़ पाते।

इस तरह ज्ञान की इस परंपरा में मानव समाज में फिर से एक भेद का उदय हुआ । पढ़े-लिखे और बिना पढ़े-लिखे या निरक्षर मनुष्य । ज्ञान मनुष्य समाज को निश्चित ही विकसित करने में मदद करता है, पर अज्ञात और अज्ञान भी मनुष्य समाज को और अधिक खोजने की दिशा में प्रेरित करता है। इसे प्रकारांतर से ज्ञान का हिस्सा माना जाना चाहिए कि व्यक्ति के भीतर इतना विवेक है कि वह कुछ नया खोजने की ओर प्रवृत्त होता है। ज्ञान, अज्ञान और अज्ञात- तीनों को ही समूची मानवीय सभ्यता की मूल आधारभूमि की तरह से ही समझा, सोचा और माना जा सकता है। मानव सभ्यता ज्ञानेंद्रियों और मनुष्य निर्मित अंतहीन विचारों की अनोखी श्रृंखला हैं, जो साकार और निराकार जगत की चेतना से सदियों से मानव सभ्यता की तरंगों को आगे भी बढ़ा रहा है और कालक्रमानुसार लुप्त भी कर रहा है।

7 दिसंबर के लिए अपडेट हुए पेट्रोल-डीजल, टंकी फुल करवाने से पहले चेक करें ताजा दाम

परिवहन विशेष न्यूज

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 7 दिसंबर 2024 (शनिवार) के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिया है। रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट होते हैं। पिछले कई महीनों से इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी शहरों में इनके दाम जस के तस बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में एक लीटर पेट्रोल-डीजल की कीमत क्या है।

नई दिल्ली। देश की मुख्य तेल कंपनियों ने 7 दिसंबर 2024 के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price) जारी कर दिये हैं। तेल की कीमतों को अपडेट करने का सिलसिला वर्ष 2017 से जारी है। हर दिन इनकी कीमतों को अपडेट किया जाता है। ऐसे में गाड़ीचालक को लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही टंकी फुल करवाना चाहिए।

आइए इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जानते हैं कि महानगर और बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Price 7 December 2024) क्या है?

महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है।

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है।

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है।

अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

नोएडाः पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्रामः पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरुः पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ः पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर

हैदराबादः पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर

जयपुरः पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर

पटनाः पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर

कैसे चेक करें लेटेस्ट रेट

वर्तमान में तेल की कीमतों पर जीएसटी (GST) नहीं लगती है। इस पर राज्य सरकार द्वारा वैट (Value Added Tax-VAT) लगाया जाता है। वैट की दरें राज्य सरकार तय करती है। यह दर हर राज्य के लिए अलग होती हैं। यही कारण है के देश के सभी बड़े शहरों में तेल के दाम अलग होते हैं।

गाड़ीचालक तेल कंपनियों की वेबसाइट और ऐप्स पर जाकर लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वह मैसेज के माध्यम से भी ताजा कीमत जान सकते हैं। इसके लिए उन्हें RSP स्पेस पेट्रोल पंप का डीलर कोड टाइप कर 92249 92249 पर भेजना होगा। इसके बाद उन्हें रिप्लाई में लेटेस्ट रेट

इस पेनी स्टॉक पर गिरी सेबी की गाज, शेयर बेचने की लगी होड़; क्या आपने भी किया है निवेश?

सेबी ने अपनी जांच में पाया कि Mishtann Foods के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गंभीर खामियां हैं। कंपनी ने कई फर्जी ट्रांजैक्शन किए और खरीद-बिक्री के आंकड़े को काफी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया। कंपनी ने जितनी बिक्री दिखाई इन्वेंट्री उसके मुताबिक बेहद कम थी। सेबी ने कंपनी उसके प्रमोटर और CMD हितेशकुमार गौरीशंकर पटेल को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है।

शेयर बाजार नियामक SEBI ने मिष्ठान फूड्स लिमिटेड (Mishtann Foods Ltd) के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उसने कंपनी, उसके प्रमोटर और CMD हितेशकुमार गौरीशंकर पटेल को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। SEBI ने अपनी जांच में पाया है कि कंपनी ने फर्जी लेनदेन और धोखाधड़ी के जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गंभीर गड़बड़ी की है।

मिष्ठान फूड्स पर क्या आरोप हैं?

SEBI ने अपनी जांच में पाया कि मिष्ठान फूड्स ने अपनी बिक्री और लेनदेन के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए। कंपनी ने जितनी बिक्री दिखाई, उसकी तुलना में इन्वेंट्री बेहद कम थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भारी अनियमितताएं मिलीं।

कंपनी के शेयरधारकों की संख्या 2018 के अंत में सिर्फ 516 थी, जो FY2025 की दूसरी तिमाही में 4.23 लाख तक पहुंच गई। SEBI ने यह भी पाया कि कंपनी के प्रमोटर हितेशकुमार पटेल ने मार्च तिमाही से लगातार शेयर बेचकर 50 करोड़ रुपये कमाए।

SEBI ने क्या एक्शन लिया है?

सिक्योरिटीज मार्केट में बैनः मिष्ठान फूड्स और उसके प्रमोटर अब अगले आदेश तक किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे और न ही नया फंड जुटा पाएंगे।

फंड लौटाने का निर्देशः मिष्ठान फूड्स को वह पैसा भी लौटाना होगा, जो उसने गलत तरीके से ग्रुप की इकाइयों और अन्य माध्यमों से जुटाया था। इसमें 49.12 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू और 47.10 करोड़ रुपये के अन्य फंड शामिल हैं।

कारण बताओ नोटिसः SEBI ने मिष्ठान फूड्स, उसके प्रमुख अधिकारियों, और 12 अन्य संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 21 दिनों में जवाब दाखिल करना होगा।

मिष्ठान फूड्स के शेयरों का हाल

सेबी के फैसले के बाद मिष्ठान फूड्स के शेयर 19.97 फीसदी गिरकर 12.42 रुपये पर बंद हुए। पिछले एक साल में इस शेयर ने 20 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 25.36 रुपये और न्यूनतम स्तर 11.77 रुपये है। इसमें सितंबर तिमाही तक प्रमोटर के पास 43.48 हिस्सेदारी थी। वहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) 5.63 फीसदी और रिटेल इन्वेस्टर्स 50.90 हिस्से के मालिक थे।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

अगर आपने भी मिष्ठान फूड्स में पैसे लगा रखे हैं, तो आपको अपने निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी सलाह लेनी चाहिए और उसके मुताबिक आगे कदम उठा नहीं चाहिए।

तेल कंपनियों ने अपडेट किया पेट्रोल-डीजल के दाम, फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिया है। रोजाना सुबह 6 बजे फ्यूल प्राइस अपडेट होते हैं। इनकी कीमत वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर तय होती है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। आइए जानते हैं कि देश के महानगरों समेत बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम कितने हैं।

नई दिल्ली। देश की मुख्य सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price) जारी कर दिये हैं। इनकी कीमत वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर तय की जाती है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 से पेट्रोल-डीजल के दाम रोज अपडेट होते हैं।

नए अपडेट के अनुसार, इस साल लोकसभा चुनाव से पहले यानी मार्च में आखिरी बार में तेल के दाम में कटौती हुई थी। इस बार 2-2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। आज भी इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी शहरों में इनके दाम जस के तस बने हुए हैं।

आइए इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जानते हैं कि महानगर और बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price 4 December 2024) क्या है?

महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है।

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है।

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है।

बाकी बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

नोएडाः पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्रामः पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरुः पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ः पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर

हैदराबादः पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर

जयपुरः पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर

पटनाः पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर

धीमी विकास दर पर सीतारमण का जवाब, तीसरी तिमाही में पटरी पर आ जाएगी ग्रोथ रेट

परिवहन विशेष न्यूज

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर 2024 में देश की आर्थिक विकास दर की रफ्तार सुस्त हो कर 5 .4 फीसदी निश्चित तौर पर दर्ज की गई है लेकिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास दोनों यह मानते हैं कि तीसरी तिमाही के बाद ग्रोथ रेट रफ्तार पकड़ लेगी। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर, 2024 में देश की आर्थिक विकास दर की रफ्तार सुस्त हो कर 5.4 फीसदी निश्चित तौर पर दर्ज की गई है लेकिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास दोनों यह मानते हैं कि तीसरी तिमाही के बाद ग्रोथ रेट रफ्तार पकड़ लेगी।

निर्मला सीतारमण यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए विकास दर में दर्ज सुस्ती पर अपनी बात कह रही थी। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही की गिरावट को क्रमिक मानने से इनकार किया है। इस गिरावट की भरपाई तीसरी तिमाही में होने की उम्मीद जताते हुए सीतारमण ने कहा है कि दूसरी तिमाही में सार्वजनिक व्यय में कमी होने, पूंजीगत खर्चे के नहीं होने जैसे कुछ कारणों से विकास दर कम हुई है। मुझे उम्मीद है कि तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2024) में इस सभी की भरपाई हो जाएगी।

भारत ग्रोथ रेट की सालाना पूर्वानुमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं होने जा रही। अगले वित्त वर्ष और इसके बाद के वर्षों में भी भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। विकास दर की गिरावट पहली तिमाही में आम चुनाव होने और पूंजीगत खर्चे में कमी होने की वजह से भी हुआ है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

सीतारमण के इस बयान से कुछ ही घंटे पहले आरबीआई गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए सालाना आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.2 फीसदी से घटा कर 6.6 फीसदी कर दिया। हालांकि उन्होंने भी यह स्वीकार किया की तीसरी तिमाही में विकास की रफ्तार तेज होगी।

डॉ. दास ने कहा कि जो भी संकेतक हैं वह बताते हैं कि दूसरी तिमाही में जो गिरावट हुई है वह अब और नीचे नहीं जाने वाली। अब इसमें सुधार के साफ संकेत है। कृषि सेक्टर और औद्योगिक गतिविधियों की स्थिति पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर) से बेहतर है।

ग्रामीण खपत में तेजी है, सरकार की खपत भी बढ़ रही है, निवेश में भी सुधार के लक्षण हैं। निर्यात में हमने 17.2 फीसदी की तेजी देखी है। सर्विस सेक्टर का निर्यात भी 22.3 फीसदी से बढ़ा है। ऐसे में तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 6.9 फीसदी और चौथी तिमाही में 7.2 फीसदी है।

अब विदेश से जमकर आएगा पैसा! RBI ने प्रवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमा पर बढ़ाई ब्याज दर

परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआई ने बैंकों को अब एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष से कम अवधि की एफसीएनआर (बी) जमाएं अल्पकालिक वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) जमा चार प्रतिशत दर पर जुटाने की अनुमति दे दी है जबकि पहले यह 2 .50 प्रतिशत थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारत के पास अपने व्यापार को डी-डॉलराइजकरने की कोई योजना नहीं है।

नई दिल्ली। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमाओं पर ब्याज दर सीमा बढ़ाने का एलान किया है। इस कदम का उद्देश्य रुपये पर दबाव के बीच पूंजी प्रवाह को बढ़ाना है। केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है।

शुक्रवार से बैंकों को अब एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष से कम अवधि की एफसीएनआर (बी) जमाएं अल्पकालिक वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) जमा चार प्रतिशत दर पर जुटाने की अनुमति दे दी है, जबकि पहले यह 2.50 प्रतिशत थी।

इसी तरह, तीन से पांच वर्ष की अवधि की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं पर एआरआर प्लस पांच प्रतिशत ब्याज दिया जा सकता है, जबकि पहले यह सीमा 3.50 प्रतिशत थी। एफसीएनआर पर यह छूट अगले वर्ष 31 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगी।

'म्यूलहंटर एआई' से बैंकों की जुड़ने की सलाह

आरबीआई ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि वे उसकी पहल 'म्यूलहंटर डाट एआइ' के साथ सहयोग करें, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल खातों (फर्जी खातों) को हटाया जा सके। म्यूल खाता एक बैंक खाता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध तरीके से पैसा लूटने के लिए करते हैं। गुमनाम व्यक्ति इन खातों को खोलकर इसमें लोगों से ठगी के पैसे जमा कराते हैं। इन खातों से धन हस्तांतरण का पता लगाना और उसे वापस पाना मुश्किल होता है।

आरबीआई ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि वे उसकी पहल 'म्यूलहंटर डाट एआइ' के साथ सहयोग करें, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल खातों (फर्जी खातों) को हटाया जा सके। म्यूल खाता एक बैंक खाता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध तरीके से पैसा लूटने के लिए करते हैं।

डी-डॉलरीकरण को योजना नहीं: दास

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारत के पास अपने व्यापार को 'डी-डॉलराइज' (de-dollarization) करने की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है कि भारत दूसरे साथ के साथ व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल घटाने की दिशा में नहीं बढ़ रहा है।

आरबीआई गवर्नर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने का विकल्प चुनते हैं तो उन पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा ब्रिक्स मुद्रा के बारे में दास ने कहा कि यह समूह के सदस्यों द्वारा दिया गया एक विचार है, लेकिन इस पर कुछ चर्चाओं के अलावा कोई प्रगति नहीं हुई है।

सोने का नहीं बदला भाव, चांदी हुई सस्ती; चेक करें लेटेस्ट प्राइस

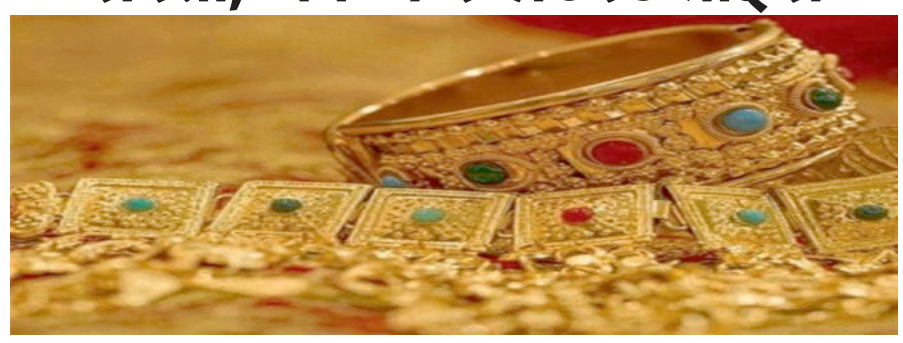

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिका से गैर-कृषि पेरोल और बेरोजगारी के महत्वपूर्ण आंकड़े आने वाले हैं। उससे पहले गोल्ड ट्रेडर्स ने अतिरिक्त सतर्कता दिखाई और अधिक खरीदारी या बिक्री से परहेज किया। सोने की कीमत 79150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। हालांकि चांदी 300 रुपये घटकर 93500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। आइए जानते हैं कि अब सोना किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

नई दिल्ली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं, चांदी के भाव में गिरावट आई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 79,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। हालांकि, चांदी 300 रुपये घटकर 93,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। गुरुवार को सफेद धातु 93,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। शुक्रवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 78,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर वायदा कारोबार में फरवरी डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों में 181 रुपये या 0.24 प्रतिशत की तेजी आई और यह 76,657 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो गोल्ड की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

सोने की कीमतों पर क्या है एक्सपर्ट की राय

एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, ₹आज शाम को बाजार में गैर-कृषि पेरोल और बेरोजगारी के महत्वपूर्ण आंकड़ों का इंतजार है। इसलिए एमसीएक्स पर सोने में मामूली बढ़त दर्ज की गई। फेड के नीतिगत दृष्टिकोण को आकार देने के लिए ये मीट्रिक महत्वपूर्ण हैं।"

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ₹अमेरिका में उम्मीद से बेहतर मैक्रोइकॉनोमिक डेटा फेड को इस महीने दरों में कटौती रोकने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका सोने की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, उम्मीद से कमजोर डेटा सोने की कीमतों में उछाल ला सकता है।"

भू-राजनीतिक तनाव पर भी रहेगी नजर

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कमोडिटी रिसर्च के विश्लेषक मानव मोदी ने कहा, ₹डॉलर में कमजोरी और शुक्रवार को आने वाली प्रमुख नौकरियों की रिपोर्ट से पहले सोने में स्थिरता बनी हुई है। भू-राजनीतिक अशांति लगातार बढ़ रही है, जिससे सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों के लिए मजबूत आधार तैयार हो रहा है।' फ्रांस की सरकार गिर गई, जबकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक-योल के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू करने का असफल प्रयास किया था। मोदी ने कहा कि अमेरिका से लगातार कमजोर आंकड़ों की रिपोर्ट के बाद डॉलर में गिरावट आई, जो गोल्ड के लिए अच्छी बात है।

बांग्लादेश में हिन्दुओं का आर्तनाद और भारत सरकार की भूमिका : राकेश अचल-विभूति फीचर्स

बांग्लादेश में आज हो रहे घटनाक्रम को देखकर मुझे 53 साल पहले की वे घटनाएं याद आ रहीं हैं जो बांग्लादेश बनने के पहले पाकिस्तान के बंगाल में हो रही थीं। उस दौर में भी तत्कालीन पाकिस्तानी सत्ता ने बंगालियों पर बर्बरता की तमाम हदें तोड़ दीं थीं। पीडितों का आर्तनाद सुनकर भारत की तत्कालीन सरकार ने उस समय जो कदम उठाये थे ,उनके बारे में आज कोई सोच भी नहीं सकता,तब भारत के फील्ड मार्शल मानेक शा और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आज भी बांग्लादेश में परिस्थितियां विकराल हैं और भारत की ओर से ऐसे ही कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस मामले में भारत सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

ये हकीकत है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर ज्यादती बांग्लादेश का आंतरिक मामला है लेकिन जब इस घटनाक्रम से भारत का जन मानस उद्वेलित है तो भारत की सरकार को भी कुछ तो सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत ने अघोषित रूप से बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण दी हुई है उसी तरह उसे बांग्लादेशी हिन्दुओं पर ज्यादतियों को लेकर बांग्लादेश की मौजूदा अस्थाई सरकार पर दबाब डालकर हिंसा को रोकने के प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसके लिए बांग्लादेश पर हमला किया जाये ,लेकिन बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी तो दी ही जा सकती है।

भारत में चौतरफा धर्मध्वजाएं लेकर मार्च करने वाले जनमानस और धार्मिक नेताओं को भी इस मुद्दे पर सरकार पर दबाब डालना ही चाहिए । बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है ,वो साफ़ तौर पर सत्ता पोषित है। ये सब करने की हिम्मत बांग्लादेश की सत्ता में कहाँ से आयी होगी इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए। असहिष्णुता और नफरत की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। आज बांग्लादेश में सत्तापोषित नफरत फल-फूल रही है इसीलिए भारत सरकार को इस मामले में कड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए।

हैरानी की बात ये है कि भारत की जो सरकार रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए दखल कर सकती है वो सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हो रही ज्यादतियों के मामले में दखल नहीं दे पा रही है। मुमकिन है कि उन्हें आशंका हो कि बांग्लादेश उनसे अपेक्षित सौजन्यता न दिखाए। बांग्लादेश में इस समय सत्ता की बागडोर जिन हाथों में है उन हाथों में शांति का नोबल पुरस्कार भी आ चुका है ,फिर भी वे हाथ अपने यहां साम्प्रदायिक हिंसा को नहीं रोक पा रहे हैं।

साम्प्रदायिक हिंसा बांग्लादेश में हो या किसी और देश में आसानी से रोकी भी नहीं जा सकती । हमारे यहां मणिपुर में तो साम्प्रदायिक हिंसा को डेढ़ साल हो चुके हैं। हम मणिपुर को नहीं सम्हाल पा रहे तो कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि बांग्लादेश अपने यहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर होने वाली हिंसा को सम्हाल लेगा ? साल भर पहले तक बांग्लादेश भारत का प्रिय मित्र था। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के समय उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने दिल्ली भी आयीं थीं , उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण भी दिया था ,लेकिन वे शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते बांग्लादेश जा नहीं पाये ।

बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद अंतरिम सरकार से भारत की बन नहीं पायी ,उलटे भारत-बांग्लादेश के संबंधों में कड़वाहट शुरू हुई और अब चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ़्तारी के बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी तल्ख़ कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है।

बीते दिनों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नज़रुल तो कह चुके हैं कि "भारत को ये समझना होगा कि ये शेख़ हसीना का बांग्लादेश नहीं है'। अब पता नहीं कि भारत आसिफ नजरुल की बात समझा है या नहीं ? बावजूद इसके भारत सरकार ने शेख हसीना को बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के सुपुर्द नहीं किया है। रार की असली वजह शायद यही है।

हमें याद रखना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश चार हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं और दोनों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से लगती है लेकिन उसकी 94 फ़ीसदी सीमा भारत से लगती है इसलिए बांग्लादेश को 'इंडिया लॉक्ड' देश कहा जाता है। इतना ही नहीं बीते कुछ सालों में बांग्लादेश, भारत के लिए एक बड़ा बाज़ार बनकर उभरा है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।

वर्ष 2022-23 में बांग्लादेश भारत का पांचवां सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार बन गया। वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 15.9 अरब डॉलर का था।

अब भारत के सामने एक ही विकल्प है कि भारत बांग्लादेश को अपना भूभराकर स्वरूप दिखा। हड़काये ,पाबंदियां लगाए, अंतर्राष्ट्रीय दबाब बनाये ,अन्यथा बांग्लादेश भी पाकिस्तान के बाद भारत का एक स्थाई दुश्मन बन जायेगा। बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता का झुकाव इस समय भारत के बजाय चीन की ओर है , तय है कि बांग्लादेश इसीलिए भारत के दबाब में आ नहीं रहा है।भारत को बांग्लादेश के मौजूदा शासकों को अतीत की याद दिलाना चाहिए। यदि भारत की मौजूदा सरकार बांग्लादेशी हिन्दुओं की हिमायत करने में नाकाम रही तो आप तय मानिए कि बांग्लादेश में हिन्दुओं का कोई खैरख्वाह नहीं बचेगा। पहले से विदेश नीति के मोर्चे पर हिचकोले खा रहे भारत के लिए ये एक मौक़ा है जब वो अपना वजूद प्रमाणित कर सकता है। देखिये आने वाले दिनों में बांग्लादेशी हिन्दू राहत की सांस ले पाते हैं या नहीं ?

ओडिशा की महिलाओं ने रचा नया ट्रेंड: सुभद्रा योजोना से रुपये लेने की इंकार किया 18 हजार महिला

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : राशन कार्ड, आवास, भत्ते जैसी सामाजिक सहायता योजनाओं में कई अयोग्य लाभार्थी शामिल हैं। लेकिन अब ओडिशा के हजारों लाभार्थियों ने सुभद्रा रुपये न लेने का फैसला किया है और एक नया चलन स्थापित किया है।आपको पता ही होगा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में हजारों भूत लाभार्थी शामिल हैं।उन्होंने यह खबर सुनी होगी कि उन्हें पात्रता सूची में शामिल किया गया और उन्हें आवास, राशन और भत्ता मिला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुभद्रा योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले 1 करोड़ 5 लाख 36 हजार 612 आवेदकों में से करीब 18 हजार 735 महिलाओं ने 3 दिसंबर तक आवेदन वापस ले लिया है। महिलाओं की ऐसी पहल सराहनीय है।

जो लाभार्थी योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, उनके लिए सुभद्रा वेबसाइट पर ऑप्ट-आउट की सुविधा है। यह अभी भी चल रहा है। बड़ी बात यह है कि इस वेबसाइट पर जाकर 18,000 से ज्यादा महिलाएं बाहर हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं की ऐसी पहल ने एक नया चलन स्थापित किया है।इनमें सुभद्रा प्रथम किस्त की चौथी किस्त का भुगतान 25 दिसंबर को करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। इसके लिए नये आवेदकों समेत जिन आवेदकों को अब तक सहायता नहीं मिल पायी है, उनके आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है। दूसरी ओर, सुभद्रा एक गरीब महिला है जो सड़कों पर उतर आई है। गजपति रायगढ़ा ब्लॉक के हातिबाड़ी गांव की महिलाओं ने सड़क जाम कर आंगनवाड़ी दीदी को हिरासत में ले लिया।

प्लान पर हुई चर्चा

प्रयोगधर्मी के नेतृत्व में कांग्रेस को नए सिरे से,
मजबूत करने के प्लान पर हुई चर्चा।
सभी थे चिंतित की लोकसभा में
पार्टी का बना रहे विपक्ष का दर्जा।
कई सालों से पार्टी की हो चुकी हालत खस्ता,
अड़ानी-अड़ानी करते भटक गए रस्ता।
कई राज्य जीते-जीते हारे,
हरियाणा-महाराष्ट्र में हो गए वारे-न्यारे।
देखते रह गए मुख्यमंत्री बनने के सपने,
देखो हराकर चल दिए अपनो को अपने।
वैसे तो खड़गेजी के हाथ में है कमान,
तीर चलाए राहुलजी, प्रियंका बनी महान।
ज्ञान देते बाबा संविधान का,
नहीं फूके जाते अब पार्टी में प्राण।
मुद्दे बदलो संकट से उबारों,
यारों तभी आएगी पार्टी में जान।

संजय एम. तराणेकर

कभी हार ना मानने का हौसला देते हैं पूज्य डॉ. बाबा साहेब

आज के युवा जमकर उनके विचारों को पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

आगरा,संजय साग़र सिंह। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाने वाले पूज्य डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। हर साल पूज्य बाबा साहेब की पुण्य तिथि के इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के संविधान निर्माता थे। उनकी अध्यक्षता में ही दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया गया था।

संविधान शिल्पी, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस (पुण्य तिथि) पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने कहा, ₹डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि पूज्य डॉ बाबासाहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जीवनभर जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया।

आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन, उनका संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान और समान अधिकार मिलने चाहिए, और इसके लिए हमें लगातार संघर्ष करना होगा। आज, उनके योगदान को याद करना और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि हम समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को मजबूत कर सकें।

उन्होंने आगे कहा, ₹डॉ. बाबा साहेब कभी हार ना मानने का हौसला देते हैं। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके महत्वपूर्ण विचार और राष्ट्रवादी चिंतन एवं कथन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज के युवा जमकर उनके विचारों को पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उनके योगदान और उनके विचार भारतीय समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल संविधान निर्माता थे, बल्कि उन्होंने समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को प्रबल किया। उनके जीवन और विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।₹

उन्होंने यह भी कहा, ₹डॉ बाबा साहेब ने जिन मुद्दों पर जोर दिया, जैसे कि शिक्षा और महिलाओं के अधिकार, वे आज भी समाज में प्रासंगिक हैं। उनका प्रसिद्ध उद्घोष ₹शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो₹ आज के युवा समाज को जागरूक करने का एक सशक्त मंत्र बन चुका है। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है, जो समाज में बदलाव ला सकता है, और इसी कारण उन्होंने शिक्षा की महत्ता को हमेशा प्राथमिकता दी।

श्री खान ने कहा, ₹वे समाज में समानता की आवश्यकता पर बल देते थे, और यही कारण था कि उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद और अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं के उत्थान की दिशा में भी कई अहम कदम उठाए, यह सोचते हुए कि एक समाज की प्रगति को उस समाज में महिलाओं की स्थिति से मापा जाना चाहिए। उनका यह विचार आज भी सामाजिक सुधारक और कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक है।₹

अंत में वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने कहा, परिनिर्वाण का अर्थ बौद्ध धर्म में किसी व्यक्ति के जीवन के दुखों और सांसारिक मोह से मुक्त होने से जुड़ा है। डॉ. अंबेडकर जी चाहते थे कि समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक असमानताओं का अंत हो। उनके जीवन और विचारों से यह स्पष्ट है कि समाज सुधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है।

शांति, सौहार्द, समरसता और भाईचारे क़ायम रखते हुए अल्पसंख्यकों को एक नया स्वतंत्र देश बनाकर देना चाहिए : समाजिक चिंतक राजू शर्मा

आगरा,संजय साग़र सिंह। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय (हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई) पर हो रहे हमालों, अत्याचारों और हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए समाजिक चिंतक राजू शर्मा ने कहा, ₹बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो, शांति, सौहार्द, और भाईचारा क़ायम करने के लिए उन्हें एक नया स्वतंत्र देश बनाकर देना चाहिए। एक नया स्वतंत्र देश देना विश्व में शांति, सौहार्द और भाईचारा क़ायम रखने में एक बहुत बड़ा और अल्पसंख्यकों के हित में सराहनीय कदम होगा। आज़ बांग्लादेश में शांति सौहार्द, समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता हैं। बांग्लादेश की सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या को हल करना ही वहां के असुरक्षित अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर होगा।

श्री शर्मा ने आगे कहा, ₹बांग्लादेश में अब तक का सबसे बड़ा संकट यह है कि विशेष रूप से हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि अल्पसंख्यक समुदाय, इस समय कट्टरपंथियों के हमलों और हिंसा का शिकार हो रहा हैं। मंदिरों पर हमले, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि व्यापारियों और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा हैं। यह स्तिथि बांग्लादेश के व्यापार और विकास के रास्ते में कितना बड़ा अवरोध उत्पन्न करेगा, इसकी वर्तमान सरकार और कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। यह स्थिति

बांग्लादेश के लिए न केवल एक आंतरिक संकट है, बल्कि व्यापार, उसकी विदेश नीति और वैश्विक छवि पर भी बहुत खराब असर डाल रही है, खासकर यह कट्टरपंथी रुझान और मानवाधिकारों का उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के खुलकर सामने आ गया हैं, और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, इससे कारण बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंध इस समय बहुत खराब हो रहे हैं, इसका व्यापक असर बांग्लादेश के कारोबार पर भी पड़ रहा हैं, और वो भी जल्द ही ग़रीबी, भुखमरी और कंगाली की कगार पर आ जायेगा। अगर जल्द ही बांग्लादेश अपनी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका, तो यह देश के आर्थिक विकास एवं व्यापार के लिए खतरे की घंटी साबित होंगी। इसलिए यह जरूरी है कि बांग्लादेश सरकार जल्द ही इस स्थिति को संभाले और विशेषकर अल्पसंख्यकों, की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए अगर बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की नहीं कर सकती तो उन्हें एक नया स्वतंत्र देश प्रदान किया जाना चाहिए।₹

बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यकों की असुरक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए समाजिक चिंतक राजू शर्मा के हुए कहा, ₹इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश सरकार से हमले और हिंसा रोकने का आग्रह करता हूं। बांग्लादेश के करोड़ हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई अल्पसंख्यको को समुंदर में नहीं फेंका जा सकता है। बांग्लादेश की सरकार को करोड़ हिंदू, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यको के साथ भाईचारा कायम रखते हुए समान व्यवहार करना चाहिए। बांग्लादेश करोड़ हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई अल्पसंख्यको का भी देश है। लेकिन आज़, वह पवित्र मंदिरों को तोड़ा जा रहा हैं और साधु संतों को बेबजह जेल में डाला जा रहा हैं। बेकसूर महिलाओं और मासूर बच्चों पर अमानवीय अत्याचार और हमले कर उन्हें मारा जा रहा हैं। बांग्लादेश सरकार, सेना, पुलिस और प्रशासन को वहां रह रहे करोड़ हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई अल्पसंख्यको की भलाई और उन्हें शैतानों से बचाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर बांग्लादेश की सरकार, सेना, पुलिस और प्रशासन करोड़ हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई अल्पसंख्यको की सुरक्षा नहीं कर सकता तो, शांति, सौहार्द, समरसता और भाईचारे क़ायम रखते हुए उनके लिए एक नया स्वतंत्र देश बनाकर दे देना चाहिए।

भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा निर्माता

सुनील माहला

पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में एक बहुत ही गंभीर और बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए या यूं कहें कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार पिछले कुछ समय से देश में इलेक्ट्रोनिक वाहन (ईवी) को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने 'ईवी तकनीक' में भारी निवेश किया है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, और इसका बहुत बड़ा कारण पेट्रोल की कीमतों की स्थिति, तथा वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चिंताएं हैं। आज आम व खास दोनों का ही रूझान भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद की ओर लगातार बढ़ा है, क्यों कि एक तो इन वाहनों पर सब्सिडी मिल जाती है, दूसरे छोटे वाहनों का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है या इनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2022 में भारत के आधे से अधिक तिपहिया पंजीकरण इलेक्ट्रिक वाहन थे, जो ईवी अपनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है। वर्तमान में हमारी सरकारें देश में बड़े शहरों में ई-चार्जिंग स्टेशनों को भी बढ़ावा देने की ध्यान दे रही है और अनेक शहरों में तो इनकी शुरूआत भी हो चुकी है। बहरहाल, यह ठीक है कि इलैक्ट्रिक वाहनों में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने और जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला कर सकने की अभूतपूर्व क्षमताएं है और ये तेल आयात को भी कम करने में मदद करते हैं और ऊर्जा विविधता लाने में भी योगदान करते हैं, कांपैक्ट डिजाइन के कारण शहरों में भीड़भाड़ कम करने में भी मदद करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इलैक्ट्रिक वाहनों से हमारे पर्यावरण, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर कहीं न कहीं विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में आज इतनी अधिक संख्या में देश की मांग के अनुरूप ईवी बैटरी उत्पादन से हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।इससे धरती पर जैव-विविधता की हानि, वायु प्रदूषण और मीठे पानी की आपूर्ति में कमी जैसे प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक नई कारों की बिक्री का 52% हिस्सा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा। इलैक्ट्रिक वाहन बड़ी बैटरियों से चलते हैं, और मुख्य चिन्ता यह है कि चार्जिंग के अलावा, इलैक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) उत्पादन से भी कार्बन उत्सर्जन होता है। आंकड़े बताते हैं कि 43 किलोवाट-घंटे की औसत क्षमता के साथ, केवल एक ईवी बैटरी का उत्पादन करने से लगभग उतना ही कार्बन उत्सर्जन होता है जितना कि एक गैसोलीन कार को लगभग 50,000 मील चलाने से होता है। बैटरियों में पाये जाने वाले लिथियम और निकल भी कार्बन पदचिह्न में योगदान करते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि बैटरी निर्माण प्रक्रियाओं का पर्यावरण पर काफी प्रभाव पड़ता है। दरअसल, ईवी की लिथियम-आयन बैटरी के घटकों को खनन करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों को आसानी से रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, जो दुनिया भर में बढ़ती ई-कचरे की समस्या को बढ़ाता है। अतः कहना ग़लत नहीं होगा कि इलैक्ट्रिक वाहनों में भी अपशिष्ट की समस्या एक बड़ी समस्या है, जो मनुष्य के लिए एक चुनौती है। यह ठीक है कि लिथियम-आयन बैटरियां हमारी अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनका अपशिष्ट इतना होता है कि जीवाश्म ईंधन पर उनका कोई विशेष फायदा नजर नहीं आता है। एक आंकड़े के अनुसार लिथियम-आयन अपशिष्ट की यह संख्या वर्ष 2030 तक लगभग 3.2 मिलियन टन तक पहुँच जाने की संभावनाएं हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक ई-कचरा मॉनिटर 2020 के अनुसार, भारत, जो पहले से ही एक बड़ी ई-कचरे की समस्या से जूझ रहा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कचरा उत्पादक है। सरकार की इलैक्ट्रिक वाहनों की पहल पर्यावरण के लिहाज से ठीक है लेकिन इलैक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों का अनुचित तरीके से निपटान भारत में ई-कचरे की बढ़ती समस्या में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जिससे ईवी (इलैक्ट्रिक व्हीकल) क्रांति के साथ-साथ पर्यावरणीय चिंताएँ भी बढ़ सकती हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि हम ई-कचरे के निपटान की दिशा में भी उचित एवं सकारात्मक कदम उठायें।

'जो 26/11 पर होना चाहिए था, वो बालाकोट-उरी में हुआ'; आतंकी घटनाओं पर और क्या बोले जयशंकर ?

जयशंकर ने कहा कि भारत इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ यह अपनी परंपराओं को लेकर प्रतिबद्ध बना हुआ है तो दूसरी तरफ भविष्य की ओर देखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि आज हम आतंकवाद का जिस तरह से जवाब दे रहे हैं वो बदलाव को दिखाता है।

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ यह अपनी परंपराओं को लेकर प्रतिबद्ध बना हुआ है, तो दूसरी तरफ भविष्य की ओर देखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है।

उरी और बालाकोट से दुश्मन को मिला साफ संदेश

जयशंकर ने कहा कि आज हम आतंकवाद का जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, उसे देखिए। एक देश जिसने 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले का भी जवाब नहीं दिया, वह आज उरी और बालाकोट में कार्रवाई के जरिये स्पष्ट संदेश दे रहा है।

राजनयिक से राजनेता बने जयशंकर को एक निजी चैनल द्वारा आयोजित इंडियन आफ द इयर कार्यक्रम में इंडिया फर्स्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि यह विदेश मंत्री बनने का अच्छा समय है।

देश का चेहरा बनना सौभाग्य की बात

जयशंकर ने आगे कहा कि भारत इस समय वैश्विक विमर्श को आकार दे रहा है और चीन के साथ सीमाओं पर चुनौतियों का दृढ़ संकल्प के साथ सामना कर रहा है। ऐसे समय में विदेश में देश का चेहरा बनना सौभाग्य की बात है।

उन्होंने कहा कि आज हमारे पास चयन के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रतिनिधि हैं। भारत के हर हिस्से में जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर है। यह सफलता कोई अभिजात्य या महानगरीय चीज नहीं है।

विदेश मंत्री ने कहा, क्वाड को आगे बढ़ाने का श्रेय ट्रंप को

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पारंपरिक नीतियों को तोड़ने की कोशिश में है, क्वाड संगठन को उनके समर्थन को लेकर आशंका जताई जा रही है। लेकिन विदेश मंत्री एस. जयशंकर इन आशंकाओं को निर्मूल मानते हैं और कहते हैं कि ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब क्वाड की शुरुआत विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक के तौर पर हुई थी।

क्वाड को आगे बढ़ाने का श्रेय ट्रंप प्रशासन को ही दिया जाना चाहिए। जयशंकर शुक्रवार को भारत-जापान फोरम में एक चर्चा में हिस्सा लेते हुए क्वाड पर अपना विचार रख रहे थे। उन्होंने कहा कि क्वाड की शुरुआत ट्रंप प्रशासन के दौर में ही हुई थी। ट्रंप प्रशासन के पहले वर्ष में पहली बार क्वाड देशों के उप-विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023